राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 29 अंक : 4

जुलाई–अगस्त, 2006

राष्ट्रवादी छात्र आन्दोलन के 57 वर्ष...

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्

पुणे (महाराष्ट्र) में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक का उद्घाटन करते परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. कैलाश शर्मा एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री के. रघुनंदन।

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में उपस्थित सदस्यगण।

बैठक के दौरान आयोजित सार्वजनिक समारोह में मंचासीन मुख्य अतिथि डा. एस.एफ. पाटिल (बीच में)

रानीखेत में अभाविप उत्तरांचल की वार्षिक स्मारिका के विमोचन के अवसर पर उपस्थित जिला प्रमुख डा. प्रवीण विष्ट, राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री श्री अतुल कोठारी, क्षेत्रीय विधायक श्री अजय भट्ट, छावनी परिषद रानीखेत के अधिशासी अधिकारी श्री डी.एन. यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण बहुगुणा।

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका
वर्ष : 29 अंक : 4, ● जुलाई–अगस्त, 2006

संरक्षक
अतुल कोठारी

प्रबंध संपादक
नितिन शर्मा

संपादक मंडल
डा. मुकेश अग्रवाल
संजीव कुमार सिन्हा
आशीष कुमार 'अंशु'
उमाशंकर मिश्र

डा. रंजीत ठाकुर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बी–50, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, दिल्ली–110007 के लिए प्रकाशित एवं पुष्पक प्रेस, 119, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, ओखला, फेज–1, नई दिल्ली–20 द्वारा मुद्रित

फोन : 011 – 27666019, 27662477
E-mail : chhatrashakti@yahoo.co.in
Website : www.abvp.org

मूल्य : एक प्रति रुपए 10/–

शुभकामना

"राष्ट्रीय छात्रशक्ति" की ओर से सभी पाठकों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 59वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं।

विषय सूची

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक सम्पन्न..... 6

राष्ट्रवादी छात्र आन्दोलन के 57 वर्ष..... 12

शैक्षिक परिदृश्य
असफल रही है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था..... 17

जयंती
अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद..... 19

साक्षात्कार
विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. कैलाश शर्मा..... 21

परिचर्चा
आजादी के उनसठ साल..... 22

शिक्षा में नए प्रयोग
देव संस्कृति विश्वविद्यालय..... 24

परिषद गतिविधियां..... 25

Special on Shri Guruji 28

साथ में– कविता/स्मरणांजलि/Martyrdom of Karyakartas

आह्वान

- ***क्या आप देश की वर्तमान दशा पर चिन्तित हैं?***
- ***क्या आपको दृढ़ विश्वास है कि सामाजिक परिवर्तन लाने में छात्र-युवा ही सक्षम हैं?***

यदि हां

- ***तो अपने क्षोभ को शब्द दीजिए और विश्वास कीजिए, आपमें क्षमता है कलम की नोंक से दुनिया का रुख बदलने की।***
- ***अपने विचारों को साहित्य की किसी भी विधा में शब्द दें तथा राष्ट्रीय छात्रशक्ति द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बी-50, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, दिल्ली-110007 को प्रेषित करें।***

मां तुम्हें पुकारती

–सरिता मेहरा, राष्ट्र सेविका गिति

हार कर तुम थक न जाना, कटकों में फंस न जाना
हर निशा के बाद उजाला है, हर उषा के बाद सवेरा है
मां भारती, उठो, आज तुम्हें पुकारती
चारो तरफ है खण्ड विखण्ड, ज्वाला भड़की आज प्रचण्ड
कहीं जल रही संस्कृति, कहीं जले इतिहास है
कहीं नग्न हो रही मां सरस्वती,
कहीं उठता मीरा का उपहास है
कहीं बनायें पद्मावती का जौहर भी बकवास है
सत्य सनातन, आर्यपुत्रों को, नौ भक्षक बता रहे हैं
राम–कृष्ण अवतारों पर भी, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं
गुरुवरम्परा को अपमानित कर,
हर हृदय पर चोट लगा रहे हैं
जालिम गौरी, औरगजेब को,
न्यायाधीश और जिन्दापीर बता रहे हैं।
लुटेरा बन गये आज शिवाजी, अकबर महान बता रहे हैं
स्वतन्त्रता पर मिटने वाले को आतकवादी बता रहे हैं
अपमान किया महाभारत का रामायण को झूठा बोला
जाटों को जालिम और भगवा रंग मे भी विष घोला
लूट बताते जैन धर्म के पूज्यवर तीर्थंकर को
कैसा तक अपमान सहोगे, कितने लाछन और सहोगे?
नाकर कॉले पुत्रो को न लाज रही न शर्म रही
अपने ही अपनी कब्रें खोद रहे हैं,
चिर पुरातन सस्कृति पर कालिख पोत रहे
कालजयी संस्कृति के वारिस तुम,
दुनिया को दिव्य दृष्टि देते
आज तुमको ही नीचा दिखा रहे हैं
गर, अब भी खून नही खौला,
गर वीर भुजायें नहीं फड़की
तीव्र प्रचण्ड ज्वाला से, हृदय की आग नहीं भड़की
तो जीवन व्यर्थ तुम्हारा है, नहीं लजाओ दूध मां का
तुम्हें शपथ मां के आंचल की,
पूर्वजों के पौरूष के ललकार की
माटी का हर कण चीत्कार रहा है,
उखाड दो आज तुम ललकार दो
गर कहीं इतिहास का गद्दार है, तो उसका समूल नाश हो
इतिहास यज्ञ में पूर्णाहुति बन,
तिल–तिल हमको जलना होगा
हृदय–हृदय की आग को एक ज्वाला बनना होगा।
हार कर तुम थक न जाना, कटकों में फंस न जाना
हर निशा के बाद उजाला है, हर उषा के बाद सवेरा है।■

स्मरणांजलि

स्व० यशवंतराव केलकरजी ने अपना पूरा जीवन समाज परिवर्तन के महती कार्य में लगा दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शिल्पकार एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लब्धप्रतिष्ठ स्वयंसेवक के रूप में वे निरंतर एक मजबूत संगठन बनाने एवं लोकसंग्रह के कार्य में जुटे रहे। उनके स्नेहिल सान्निध्य से अनेक कार्यकर्ताओं का जीवन मिशन के रूप में परिणत हुआ। उनके जीवन का हर क्षण कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता था। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री केलकर जी की पुण्य स्मृति में कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभवों को "पूर्णांक की ओर" नामक पुस्तक में शब्दांकित किया है। प्रस्तुत है इस पुस्तक से उद्धृत प्रेरणास्पद अनुभव :–

स्व० यशवंतराव केलकर

1974 ई में आयोजित विद्यार्थी परिषद का रजत जयंती समारोह मुंबई में बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ। पूरे देश से प्रतिनिधि आए थे। सफल समारोह के बाद पत्रकार वार्ता भी हुई। एक पत्रकार ने पूछा, अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि उपस्थिति थे? मैंने बड़े जोश और गर्व से कहा, सात हजार।

पत्रकारों ने और भी कई प्रश्न पूछे। पत्रकार परिषद समाप्त होने के बाद यशवंतरावजी ने पास बुलाकर धीरे से पूछा, अरविंद, कार्यालय से इस अधिवेशन में आए निश्चित प्रतिनिधियों की निश्चित संख्या कितनी मालूम हुई है? मैंने कहा, छ हजार दो सौ उन्नीस। तब तुमने पत्रकारों को सात हजार संख्या कैसे बता दी? यशवंतरावजी ने चिंतित स्वर में पूछा। कुछ नहीं मैंने केवल राउंड फिगर बता दिया। मैंने बड़ी बेफिक्री से जवाब दिया।

अरे भाई हमें सदा यथा तथ्य बोलना चाहिए। वह हितावह होता है, अन्यथा बढ़ाचढ़ाकर असत्य वृत्त देने की व्यर्थ आदत लग जाती है। उसके कारण अपना और संगठन का भी नुकसान होता है।

लोगों को अच्छा लगे या अपना सम्मान बढ़े इसलिए आंकड़ेबाजी या बढ़ाचढ़ाकर बातें नहीं करनी चाहिए, इसका वे सदा आग्रह रखते थे। ■

बेलगाम महंगाई का चौतरफा असर

देश की आजादी के उनसठ वर्ष पूरे हो रहे हैं लेकिन हमारा देश अनेक समस्याओं से घिरा हुआ हैं। प्रमुख रूप से आतंकवाद और महंगाई के कारण देश भर में अराजकता का माहौल कायम हो रहा हैं। दैनिक जीवन की जरूरतों–चावल, दाल, गेहूं, सब्जी, तेल जैसे खाद्य पदार्थों के दामों में 20–25 प्रतिशत वृद्धि से लोगों का जीवन कठिन होता जा रहा है। वहीं डीजल और पेट्रोल के दाम सातवीं बार बढाए जाने से देश भर में हाहाकार मचा हुआ हैं।

'कांग्रेस का हाथ–आम आदमी के साथ' का राग अलापने वाली कांग्रेस पार्टी और सर्वहारा के हितों का दंभ भरने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां पूरी तरह बेनकाब हो गई हैं। सत्ता मद में चूर यूपीए सरकार जनता को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। उदारीकरण के पैरोकार अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहे है। सरकार ने जिस आर्थिक सुधारों का सहारा लिया है उससे एक खास वर्ग को ही फायदा मिल रहा है, जबकि समाज के बड़े हिस्से को आज भी बुनियादी सुविधाएं मयस्सर नहीं हैं।

यह समझ से परे है कि सेंसेक्स की सनसनाती उछाल के बाद भी सौराष्ट्र, मालवा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सैकड़ों किसान आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हो रहे है? एक अनुमान के मुताबिक विश्व के अमीर लोगों की सूची में भारत के अमीरों की संख्या बढ़ी हैं लेकिन आज भी आबादी का 30 फीसदी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को अभिशप्त हैं। हवाई जहाज का किराया, कार आदि सस्ते हो रहे है जबकि रोजमर्रा जरुरतों की चीजें महंगे हो रहे है।

सुरसा की मुंह की भांति बढ़ रहे महंगाई से लोगों के घर का बजट बिगड़ गया हैं। बहुतांश लोग दो वक्त की रोटी जुटाने में ही उलझे हुए हैं। यूपीए सरकार आवश्यक वस्तुओं को सर्वसुलभ दाम पर उपलब्ध करायें, अन्यथा बढ़ती महंगाई उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं।

• 9 जुलाई विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस हैं। गत 57 वर्षों से परिषद महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सक्रिय हैं। परिषद की गौरवशाली उपलब्धियों पर क्रमबद्ध रूप से एक सारगर्भित लेख इस अंक में प्रस्तुत हैं। इसके साथ गत 25 मई से 28 मई तक पूणे में संपन्न राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में पारित किए गए चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव का पूरा पाठ भी प्रकाशित कर रहे हैं।

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक संपन्न

महाराष्ट्र की ऐतिहासिक नगरी एवं वर्तमान में देश के प्रमुख शिक्षा केन्द्र के रुप में प्रसिद्ध पूणे नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक 25 मई से 28 मई 2006 को सम्पन्न हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. कैलाश शर्मा एवं राष्ट्रीय महामंत्री के. एन. रघुनंदन ने बैठक का संयुक्त रूप से संचालन किया। कुल 190 सदस्य (17 छात्राएं एवं 53 प्राध्यापक) उपस्थित रहे। बैठक में चार प्रस्ताव पारित किए गए, जिसे हम यहां प्रकाशित कर रहे है–

प्रस्ताव-1

वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य

संप्रग सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा का तेजी से व्यापारीकरण एवं तुष्टीकरण बढा है। एक तरफ तो सरकार शिक्षा क्षेत्र में निजीकरण के नाम पर हो रहे व्यापारीकरण को रोकने में विफल रही है, तो दूसरी तरफ शिक्षा का उपयोग तुच्छ राजनीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। आज शिक्षा नीति को वोट जुटाने का साधन मानकर तुष्टीकरण किया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद् शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की राजनीति के हस्तक्षेप को मूल्य विरुद्ध मानती है तथा शिक्षा के व्यापारीकरण, अभारतीयकरण एवं शिक्षा क्षेत्र में अल्पसंख्यकवाद को पुष्ट करने वाली प्रत्येक नीति का मुखर विरोध करती है।

विद्यार्थी परिषद् केन्द्र सरकार के स्ववित्तपोषित शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण लागू करने के 93 वें संविधान संशोधन को आवश्यक मानती है। देश में स्ववित्तपोषित शैक्षिक संस्थानों में लगभग 50 प्रतिशत से भी अधिक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान है, इसलिए विद्यार्थी परिषद् की यह कार्यकारी परिषद मांग करती है कि इन संस्थानों में भी आरक्षण लागू किया जाये तथा इन संस्थानों में आरक्षण की परिधि में आने वाले एवं अन्य गरीब मेधावी विद्यार्थीयों के शुल्क की भी व्यवस्था राज्य सरकार करें तथा इसके क्रियान्वयन के लिये कानून बनाये।

केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा में किये गये वायदे खोखले साबित हुए है। अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करने का सरकार का वायदा मात्र दिखावा सिद्ध हुआ हैं। 2003–2004 मे शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 3.74 प्रतिशत खर्च हुआ था जो 2004–05 में कम होकर 3.49 प्रतिशत रह गया है। यह केंद्र सरकार के शिक्षा विरोधी रवैये को उजागर करता हे। हाल ही में आई. आई. एम. संस्थानों द्वारा शुल्क में 22 प्रतिशत वृद्धि का विद्यार्थी परिषद् विरोध करती है। केन्द्र सरकार द्वारा इन संस्थानों को करोडों रुपये अनुदान दिये जाने के बावजूद शुल्क बढाये जाने से इन संस्थानों में गरीब प्रतीभाशाली छात्र प्रवेश पाने से वंचित हो जायेंगे। विद्यार्थी परिषद् का मत है कि इन संस्थानों में स्वायत्ता बनी रहे किंतु स्वायत्ता के नाम पर उद्योगपतियों द्वारा ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों को एक प्रकार का निजी क्षेत्र बनाकर अपनी मनमानी चलाने का षड्यंत्र घातक है।

निजी शैक्षिक संस्थानों की बढती संख्या और उस पर प्रभावी अंकुश न होने के कारण छात्रों का शोषण निरंतर बढ रहा है। शिक्षा क्षेत्र में उभरते नये आयाम जैसे निजी विश्वविद्यालय, अभिमत विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं पर कोई प्रभावी नियंत्रण न होने के कारण शिक्षा का व्यापारीकरण तेजी से बढ रहा है। छत्तीसगढ निजी वि. वि. के सदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद संसद में निजी वि. वि. विधेयक अभी तक नहीं लाया गया है। निजी वि. वि. के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उडीसा, पंजाब विधानसभा में विधेयक लाया गया है। म.प्र. सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई है। इस विषय में केन्द्र सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण राज्य सरकारें असमंजस की स्थिति में है। अतः यह कार्यकारी परिषद् मांग करती है कि निजी वि. वि. विधेयक पर संसद के भीतर एवं बाहर बहस होनी चाहिये। जिससे दिशा स्पष्ट होगी।

यद्यपि केन्द्र सरकार ने GATS के अन्तर्गत शिक्षा को लाने के प्रयासों पर अभी सहमति नहीं दी है फिर भी देश के 300 से भी अधिक शैक्षिक संस्थानों के साथ समझौता (Twinning system) किया है। इस पर अंकुश रखने के लिये केन्द्र सरकार ने न कोई कानून बनाया और न ही सरकार द्वारा गठित सी.एन.आर. राव कमेटी के सुझाव को माना है। अतः विद्यार्थी परिषद् की यह कार्यकारी परिषद मॉग करती है कि केवल स्वयं के देशों में मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय एवं भारत मे नैक NAAC जैसी सस्थाओं द्वारा प्रमाणित विदेशी वि. वि. के केन्द्रों को ही खोलने की अनुमति दी जाय तथा ऐसे संस्थानो को खोलने के लिये नीति भारतीय शैक्षिक संस्थानों एव विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुये बनाई जाये।

शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया एवं शुल्क संरचना तय

करने हेतु केन्द्रिय कानून बनाये जाने की विद्यार्थी परिषद की मांग को केन्द्र सरकार ने स्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया था किन्तु निजी शिक्षा संस्थानों के दबाव में उसे लागू नहीं किया गया। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकारों को भी कानून बनाने का सुझाव दिया गया है। अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र सरकार से अविलंब केन्द्रीय कानून बनाने की मांग करती है तथा राज्य सरकारों से मांग करती है कि वे एक ही प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश एवं उचित व्यय के आधार पर शुल्क तय करने की व्यवस्था बनाये।

पूर्व में संकाय विशेष में विशिष्टता एवं उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा दिये जाने के आधार पर संस्थानों को अभिमत विश्वविद्यालय (Deemed University) का दर्जा प्रदान किया जाता था। जिसके कारण चुनिंदा शिक्षण संस्थान ही इस स्तर को प्राप्त कर पाते थे। किंतु सरकार द्वारा मानकों के साथ छेड़छाड़ किये जाने के कारण अभिमत वि. वि. की आधारभूत अवधारणा को आघात पहुँचा है। परिणामस्वरूप आज देश में अभिमत वि. वि. की संख्या बढ़कर 100 हो गयी है। इनमें से अधिकतर संस्थान व्यापार का केंद्र बन गये है, यह चिंताजनक है। अ.भा.वि.प. की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की मांग है कि अभिमत विश्वविद्यालय के वर्तमान एवं पूर्व में मानकों की समीक्षा के आधार पर रहे नए मानक तय करते हुए इन विश्वविद्यालयों को औचित्यपूर्ण बनाया जाये। ऐसे विश्वविद्यालयों से प्रताड़ित तामिलनाडु के छात्रों के प्रबल आंदोलन के बावजूद सरकार की चुप्पी छात्र विरोधी चरित्र को उजागर करती है।

देश में बड़ी मात्रा में शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के स्थान रिक्त पड़े है। जहाँ नियुक्तियाँ हुई है वहाँ भी अस्थायी या ठेके पर है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी राज्य सरकारों को शिक्षकों की नियुक्ति करने के निर्देश दिये है। अतः अभाविप की यह कार्यकारी परिषद रिक्त स्थानों पर शिक्षको की शीघ्र नियुक्ति करने एवं अतिथि व्याख्याता शिक्षकों के स्थान पर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग करती है।

छात्र संघ चुनाव हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूर्व चुनाव आयुक्त श्री लिंगदोह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। विद्यार्थी परिषद् की यह कार्यकारी परिषद् मानव संसाधन विकास मंत्रायल से मांग करती है कि आगामी शिक्षा सत्र से पूर्व समिति के दिशा निर्देशों के आधार पर छात्र संघ चुनाव हेतु आदर्श आचार संहिता बनाई जाये।

मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा संविधान विरुद्ध होकर न्यायालय की अवमानना है। केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग का गठन, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण एवं शिक्षा के साम्प्रदायीकरण का उदाहरण है। विद्यार्थी परिषद् का मत है कि अल्पसंख्यक समुदाय का हित साम्प्रदायिक शिक्षा में न होकर विज्ञान एवं राष्ट्रवाद पर आधारित शिक्षा में है। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र सरकार द्वारा तुष्टीकरण के आधार पर विद्यार्थी वर्ग में भेदभाव किये जाने वाली नीति का विरोध करती है।

सरकार 1986 की नयी शिक्षा नीति के बाद अभी तक कोई विस्तृत शिक्षा नीति नहीं तय कर पाई जबकि अधिकांश शिक्षाविदों एवं कोठारी कमीशन का ऐसा सुझाव है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद शिक्षा नीति का पुनर्विचार होना चाहिए। इस हेतु अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र सरकार से मांग करती है कि वर्तमान शिक्षा नीति की समीक्षा करते हुए हमारी आवश्यकतायें व भविष्य की संभावताएँ को ध्यान में रखते हुये नई शिक्षा नीति हेतू देशव्यापी बहस शुरु की जाये।

प्रस्ताव - 2

राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरे

अ. भा. विद्यार्थी परिषद् की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (रा.का.प.) देश की बाह्य एवं आन्तरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न हुए खतरों पर गम्भीर चिंता प्रकट करती है। देश की सीमाओं पर पाकिस्तान एव बांग्लादेश प्रेरित आतंकवाद निरंतर जारी है तो वहीं भारत एवं नेपाल के माओवादियों का परस्पर गठजोड़ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है।

लोकतंत्र की आस्था के केन्द्र संसद से लेकर धार्मिक आस्था के केन्द्र वाराणसी के संकट मोचन मंदिर पर जेहादी हमला यह सिद्ध करता है कि देश आज आई. एस. आई. (ISI) प्रेरित सुनियोजित आतंकवाद की चपेट में है। ये जेहादी विस्फोट इस बात के स्पष्ट संकेत देते है कि देश में विघटनकारी ताकतें आज पुनः देश विभाजन की मानसिक तैयारी में जुटी है जो देश की एकता, अखण्डता एवं संप्रभुता के लिए गम्भीर चुनौती है। अ. भा. विद्यार्थी परिषद की यह राष्ट्रीय कार्यकारी देश में हो रही आतंकी घटनाओं एवं आतंकवादी संगठनों के फैलते सुनियोजित जाल पर चिंता प्रकट करती है।

गत कुछ महीनों से जम्मू काश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का अचानक बढना चिंता का विषय बना है। डोडा, बसंतगढ, श्रीनगर तथा राजौरी में लगभग 50 हत्यायें कुछ ही दिनो में होना इसका स्पष्ट उदाहरण है। इन हत्याओं के पीछे मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को जम्मू काश्मीर से पलायन करने हेतू मजबूर करना है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि काश्मीर घाटी में 1993 से 2006 तक 25 नरसंहार हुये है जिसमें 500 हिंदु मारे गये है।

इन घटनाओं के कारण घाटी से इस दौरान 6000 हिंदुओं ने विस्थापन किया है। जम्मू काश्मीर पर हो रही गोलमेज वार्तायें देश विरोधी ताकतों को मजबूत बनाने की ही भूमिका निभा रही है। ऐसे मे जम्मू काश्मीर मे नेंशनल कॉन्फ्रेंस, पी. डी. पी. द्वारा पाकिस्तान के शासकों की तर्ज पर स्वायत्तता एवं सेल्फ रुल का अलाप करना तथा प्रधानमंत्री का स्वायत्तता एवं सेल्फ रुल के मुद्दे मे काम शय बनाने के आवाहन ने विघटन की आग मे घी डालने का काम किया है। तो वही काश्मीर गोलमेज वार्ता मे प्रधानमंत्री द्वारा यह कहना कि जम्मू काश्मीर से भागकर पाक अधिकृत कश्मीर (POK) मे पहुंचे आतंकवादियों को भारत में वापस आने हेतु उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों को वापस लेने की घोषणा करना सीमापार से आतंकवाद को आयात करने जैसा है। गोलमेज वार्ता में राजनीतिक दलों द्वारा कश्मीर में सेना कम करने तथा सेना का पुलिस मे हस्तक्षेप न हो यह मांग उठाना देश की सुरक्षा के लिये गंभीर चुनौती है। ऐसे अदूरदर्शी निर्णयों से जम्मू कश्मीर मे आतंकवादियों के हौसले बुलंद होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद प्रधानमंत्री द्वारा गोलमेज वार्ता में की गई इस घोषणा की कडे शब्दों मे निंदा करते हुए आतंकवाद से मुकाबला करने हेतु इस निर्णय पर पुनर्विचार तथा ग्राम सुरक्षा समितियों को सशक्त बनाने की मांग करती है।

आज देश मे लालगलियारा (रेड कोरीडोर) नाम से विकसित क्षेत्र मे नक्सलियों का जाल नेपाल से लेकर आन्ध्र प्रदेश तक फैल चुका है। दण्डकारण्य क्षेत्र में माओवादियों का बढता प्रभाव, महाराष्ट्र के गढचिरौली से छत्तीसगढ के बस्तर जिले तक फैले 90 हजार वर्ग कि.मी. के विस्तारित क्षेत्र में नक्सलवादियों द्वारा समान्तर सरकार चलाने के प्रयास इस देश की सरकार तथा सुरक्षा तंत्रों के लिए गम्भीर चुनौती है।

आंध्र प्रदेश में हाल ही में पकडा गया आधुनिक हथियारों का जखीरा जिनमें कंबोडीया और वियतनाम युद्ध के समय के व इजराइल और अमेरिका द्वारा उपयोग किये जाने वाले टिफिन बॉक्स माइन्स तथा रॉकेट लॉचर का पाया जाना एवं इनके पास एक हजार करोड रुपये के आर्थिक तंत्र का होना यह सिद्ध करता है कि नक्सलवादियों का अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी गुटो से व्यापक संबंध है। देश की सुरक्षा के सामने नक्सली आतंक की गंभीर चुनौती के बावजूद देश के प्रधानमंत्री श्री. मनमोहन सिंह का नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक मे यह कहना की सैन्य कार्यवाही न करते हुए बातचीत से हल करेंगे, केन्द्र सरकार की आतंकवाद के खिलाफ लडने की कमजोर राजनैतिक इच्छाशक्ति एवं गैरजिम्मेदाराना व्यवहार का परिचायक है। अ.भा.वि.प. की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र सरकार के इस गैरजिम्मेदारी पूर्ण रवैये की कडे शब्दों में निंदा करती है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों से मांग करती है कि नक्सल प्रभावित राज्यों में ठोस संयुक्त रणनीति बनाकर, रेड कोरीडोर में आंध्र प्रदेश से लेकर नेपाल तक फैले आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों, हथियारों के अड्डों एवं सीमा क्षेत्रों से संचालित आर्थिक तंत्र को पूरे देश में एक साथ सैन्य कार्यवाही कर ध्वस्त करे।

अ.भा.वि.प. का मानना है की देश की सुरक्षा में सरकार के साथ–साथ समाज को भी भूमिका निभानी है। असम में कुछ स्थानों पर आम जनता ने एकजुट होकर बांग्लादेशी घुसपैठियों का आर्थिक बहिष्कार कर जिस प्रकार उन्हें भागने पर मजबूर किया वह सम्पूर्ण समाज के लिए एक उदाहरण है। नक्सलवादियों के खिलाफ छत्तीसगढ के बस्तर में आम जनमानस द्वारा गैर सरकारी प्रयासों से सलवा जुडूम (शांतियात्रा), झारखंड का सेंद्रा अभियान, आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के गढचिरोली में नक्सल विरोधी अभियान इस बात को सिद्ध करता है कि देश का जनमानस आज आतंकवाद के खिलाफ सशक्त जनअभियान के लिए तैयार है। अ.भा.वि.प. की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् इसे प्रशंसा के योग्य मानते हुये आम जनता से आह्वान करती है कि वह अपने आस–पास बसे हुये इन राष्ट्रविरोधी तत्वों से सतर्क रहे तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों से मांग करती है कि आतंकवाद विरोधी इन अभियानों मे लगे आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सहायता शिविरों में रह रहे लोगों का उचित प्रबंध करे जिससे उनका मनोबल बढे।

देश की सीमायें आज चारों ओर से असुरक्षित है। पाकिस्तान द्वारा सीमापार से जारी सतत् आतंकवाद, बांग्लादेश से 3 करोड घुसपैठियों का प्रवेश, नेपाल की सीमाओं से बिहार में बड़ी संख्या में माओवादियों का प्रवेश यह सिद्ध करता है की देश की सीमायें आज आई.एस.आई. और माओवाद प्रेरित आतंकवाद का केंद्र बनी है। भारत–नेपाल सीमा पर सोनोली के समीप एक ट्रक विस्फोटक की बरामदगी जो माओवादियों द्वारा भारत में नक्सलियों एवं अन्य आतंकी संगठनों को भेजी जा रही थी। तथा 6 मार्च के वाराणसी में संकटमोचन मंदिर पर हमले के संदर्भ में पकडे गये आतंकवादियों का बांग्लादेशी नागरिक होना इस बात को सिद्ध करता है की देश की बाह्य सुरक्षा गम्भीर खतरे में है। भारत के पडोसी देश आज आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के केन्द्र बन रहे है। ऐसे में भारत सरकार का इस संदर्भ में मूकदर्शक बने रहने से स्थिति और भी विस्फोटक बनी है। अ.भा.वि.प. की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद केन्द्र सरकार से मांग करती है कि वह इन देशों के प्रति अपनी ढुलमुल विदेश नीति की पुनः समीक्षा करे तथा इन देशों को भारत विरोधी गतिविधियों को बंद करने हेतु स्पष्ट चेतावनी देकर, सीमाओं पर अपनी असरदार भूमिका का निर्वहन करे।

15 मार्च को केरल विधानसभा में तत्कालीन सत्तारूढ लोकतांत्रिक मोर्चा और प्रतिपक्ष वाममोर्चे ने कोयम्बटूर के पुरुलाबन्द बम विस्फोटों एवं 59 निर्दोष लोगों के हत्या के आरोपी अब्दुल नजर मदनी जो पिछले 8 वर्षों से कोयम्बटूर केन्द्रीय जेल में बंद है, को पैरोल पर रिहा करने का प्रस्ताव पारित किया। वोट बैंक की राजनीति के उद्देश्य से मुस्लिम तुष्टीकरण एवं न्यायालयीन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करनेवाले इस प्रस्ताव की अ.भा.वि.प. की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मांग करती है कि केरल में रिमोट कंट्रोल बम विस्फोट करने वाले आतंकवादी संगठन एन.डी.एफ. पर प्रतिबंध लगाया जाये।

अ.भा.वि.प. की राष्ट्रीय कार्यकारी का मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री तथा अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भारत-अमेरिकी असैनिक आणविक समझौते पर किये गये हस्ताक्षर राष्ट्रीय हितों को प्रभावित न कर सके इसके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि यह समझौता भारत की आणविक क्षमता को प्रभावित करेगा तथा भावी आणविक परिक्षणों को प्रतिबंधित करने वाला होगा। अ.भा.वि.प. की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद मांग करती है कि केन्द्र सरकार इस अति संवेदनशील मुद्दे पर देश के वैज्ञानिक, रक्षा विशेषज्ञ, सेना प्रमुखों तथा विदेशनीति के जानकारों से विचार विमर्श कर देश हित में निर्णय ले तथा एक दीर्घकालीन आणविक नीति बनाये।

अ.भा.वि.प. की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद देश की सुरक्षा के प्रति गम्भीर चिंता व्यक्त करते हुए केन्द्र सरकार से मांग करती है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपना गैरजिम्मेदाराना व्यवहार छोड़कर आतंकवाद के विरुद्ध कड़े कदम उठाये तथा भयमुक्त वातावरण निर्माण करने हेतु अपनी भूमिका का निर्वहन करे तथा देश की जनता से आह्वान करती है कि वह विघटनकारी ताकतों के विरुद्ध संघर्ष के लिए एकजुट हो।

प्रस्ताव - 3

केन्द्र सरकार की जन-विरोधी आर्थिक नीतियां

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद देश में बढ़ रही बेरोजगारी, महगाई, कृषि क्षेत्र की दुर्दशा तथा किसानों की आत्महत्या पर गहरी चिंता प्रकट करती है। जहाँ एक ओर 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर के दावे के आधार पर आर्थिक स्थिति में सुधार होने का दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर खाद्य पदार्थ, पैट्रोल, रसोई गैस आदि के निरंतर बढ़ते मूल्यों से आम आदमी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आम आदमी के नाम पर की जाने वाली घोषणाएं उस मुखौटे के समान है जो सरकार के आम आदमी विरोधी असली चेहरे को छुपाने का काम कर रही है।

सेवा तथा बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के दावे के बावजूद देश में बेरोजगारी का संकट गहराता जा रहा है। NSSO के 60वें राउंड का सर्वे दर्शाता है की 1993-94 में पुरुषों की बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में 5.6% से बढ़कर 2004 में 9.0% हो गयी तथा शहरी क्षेत्रों में 1993-94 में 6.7% से बढ़कर 2004 में 8.1% हो गई। इसी प्रकार महिलाओं की बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में 1993-94 में 5.6% से बढ़कर 2004 में 9.3% हो गई तथा शहरी क्षेत्रों में 1993-94 में 10.5% से बढ़कर 2004 में 11.7% हो गई। निश्चित रूप से बेरोजगारी की कुल दर 1993-94 में 7.3% से बढ़कर 2004 में 9% हो गई। 1999-2000 में देश की श्रम शक्ति 36.33 करोड़ थी, जिसकी 2006-2007 में 41.35 करोड़ तक हो जाने की संभावना है, इसके साथ ही बेरोजगारी की वृद्धि दर भी 9.79% होने की संभावना है जिससे देश में बेरोजगारों की संख्या 2.12 करोड़ हो जायेगी। जो कि निश्चित ही गंभीर चिंता का कारण है।

2006-07 के बजट में सरकार ने निर्माण क्षेत्र में कपड़ा उद्योग, खाद्यान्न प्रसंकरण (Food Processing) पेट्रोकेमिकल्स चमड़ा तथा स्वचलित वाहन उद्योग (Auto Mobile) एवं सेवा क्षेत्र में सूचना तकनीकी तथा पर्यटन को रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों के रुप में चिन्हित किया है। विद्यार्थी परिषद का निश्चित मत है कि इन क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएं है इसलिए इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नीति बननी चाहिए, परंतु इसके साथ ही कृषि क्षेत्र को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में भी रोजगार की अपार संभावनायें है। सरकार द्वारा देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पारित किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बिल 2005 पर्याप्त नहीं है। इस रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत देश के 600 में से सिर्फ 200 जिलों के हर ग्रामीण परिवार को मात्र 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की बात कही गयी है। महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि बाकी 265 दिन वह व्यक्ति क्या करेगा? देश के बाकी 400 जिलों के बेरोजगार कहां जायेंगे? इन प्रश्नों को छोड़ भी दें तो भी घोषित योजना के लिए सरकार धन मुहैया नहीं करवा रही है। इस योजना के लिए आवश्यक 40 हजार करोड़ रुपये में से बजट में सिर्फ 14300 करोड़ रुपया का ही प्रावधान रखा गया है, इनमें भी 5400 करोड़ रुपया काम के बदले अनाज योजना जो कि पहले से चल रही है, का शामिल किया गया है। इतना ही नहीं जो ग्रामीण रोजगार के लिए 2003 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.39% खर्च हो रहा था जो 2006-07 में कम होकर 0.33% रह गया है। यह आँकड़े रोजगार को लेकर सं.प्र.ग. सरकार के झूठे दावों की पोल खोलते है।

भले ही सरकार किसान हितैषी होने का दम भर रही है

परन्तु वास्तविकता यह है कि कृषि क्षेत्र जिस पर भारत की 60% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए निर्भर है, की स्थिति दिन व दिन बदतर होती जा रही है। आज जबकि अर्थव्यवस्था की विकास दर 8% आकी जा रही है, कृषि क्षेत्र मात्र 2.3% दर से ही विकास कर पा रहा है। यहां तक कि वर्ष 2005–06 के लिए खाद्यान्न का कुल उत्पादन 209.03 मिलियन टन होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है जो कि वर्ष 2001–02 से भी कम है। एक तरफ तो अपने किसानों को उचित दाम के लिए आंदोलन करने पड़ते है वहीं दूसरी ओर कहीं अधिक दाम पर विदेश से खाद्यान्न आयात किये जा रहे है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से 5 लाख टन गेहूं का आयात इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

किसानों की दुर्दशा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश भर में किसान आत्महत्या पर मजबूर हो रहे है। पिछले एक वर्ष में देश भर में 5000 से अधिक किसानों की आत्महत्या सरकार की किसान विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करती है। कृषि क्षेत्र में जिस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ प्रवेश कर रही है और राज्य सरकारों द्वारा भी उनको प्रोत्साहित करके कृषि के निगमीकरण के जो प्रयास किये जा रहे है उससे किसानों की स्थिति और बदतर हो जाएगी। कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation) जो कि 1999–2000 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% था 2004–2005 में कम होकर 1.7% रह गया है। यह दर्शाता है कि कृषि क्षेत्र खराब स्थिति में है तथा इसे भारी निवेश व ग्रामीण ऋण सहायता की आवश्यकता है।

अ.भा.वि.प. की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को रुपये को पूर्ण परिवर्तनशील बनाने के परामर्श की गंभीर निंदा करती है। एक दशक पूर्व तत्कालीन वित्तमंत्री के रूप में भी यही सलाह दी थी जो अभी प्रधानमंत्री के पद से दे रहे है। उस समय कुछ ही महीनों बाद मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनशीलता के कारण एशिया के कई देशों के आर्थिक ढांचे के ढहने से हम इस विनाशकारी विचार से बचा लिया था। परन्तु वर्तमान पहल यह दर्शाती है कि राष्ट्रीय बाजार में जोखिम का खेल खेला जायगा जो कि चिंता का विषय है। विद्यार्थी परिषद सरकार को चेतावनी देती है कि वह इस नीति को आगे ना बढ़ावे।

आज उदारीकरण के नाम पर चलने वाली आर्थिक नीतियों से देश का मजदूर, लघु उद्यमी, किसान, ग्रामीण व युवा वर्ग बदहाल होता जा रहा है। केन्द्र की सरकार द्वारा हांगकांग में हुई विश्व व्यापार संगठन की वार्ता में भारतीय हितों विशेषकर किसानों के हितों के साथ समझौता करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भूमंडलीकरण की आंधी में हमारे नीति निर्माताओं की संवेदनाएं और ईमानदारी पूरी तरह से ढह गयी है। अभी हाल ही में भारत दौरे पर आए विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पास्कल लेमी द्वारा भारत को आने वाली वार्ता में कृषि समझौता पर हस्ताक्षर करने या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी देना और हमारी सरकार की चुप्पी हमारी सम्प्रभुता पर चोट करती है। परिषद सरकार को आगाह करती है कि कृषि क्षेत्र में सब्सिडी के विषय पर सरकार कोई समझौता न करे। भले ही वामपंथी इन नीतियों पर मगरमच्छ के आँसू बहा रहे है, परन्तु सच्चाई यह है कि मनमोहन सिंह और उनके वामपंथी साथी जनविरोधी आर्थिक नीतियों के नये झंडाबरदार बन कर उभरे है। विद्यार्थी परिषद की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद सरकार को आगाह करती है कि अगर उसने अपनी जनविरोधी आर्थिक नीतियां न बदली तो उसे देश की जनता विशेषकर युवाओं के आक्रोश का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

प्रस्ताव - 4

आरक्षण एक ऐतिहासिक आवश्यकता

देश में शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था समाज के सभी वर्गों की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सहभागिता का संवैधानिक समाधान है। यह सैकड़ों वर्ष पूर्व से विविध कारणों से समाज का जो वर्ग सामाजिक सम्मान एवं सहभाग की दृष्टि से पिछड़ गया उसको सम्मान एवं न्याय देने का एक प्रभावकारी साधन है। अतः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े जातियों का आरक्षण एक ऐतिहासिक अनिवार्यता है एवं संविधान की परिधि व सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में उसे लागू करना भी आवश्यक है।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा गत दिनों पाँच राज्यों के चुनाव के ठीक पूर्व हड़बड़ी में केन्द्रीय उच्च संस्थानों में अन्य पिछड़े जातियों को आरक्षण देने की जो घोषणा की गई वह वोटों की राजनीति से प्रेरित एवं प्रभावित है। अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद आरक्षण को राजनीतिक स्वार्थपूर्ति का हथकंडा बनाये जाने की तीव्र निंदा करती है।

अभाविप देशभर में आन्दोलनरत मेडिकल छात्रों से भी अपील करती है कि आरक्षण की ऐतिहासिक आवश्यकता को स्वीकारते हुए वे स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित न करते हुए बातचीत हेतु आगे आकर इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान हेतु रचनात्मक भूमिका निभाये।

अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद समस्या के दूरगामी समाधान हेतु सरकार से मांग करती है कि –

1. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, अभिमत विश्वविद्यालयों तथा

। अखिल भारतीय केन्द्रीय संस्थानो मे सभी स्तर पर अन्य पिछडो के लिए आरक्षण लागू किया जाए।

2 आरक्षण को प्रभावी, वास्तविक एव संविधान सम्मत बनाने के लिए निजी शिक्षण संस्थानो मे आरक्षण के प्रावधान करने वाले विधेयक की परिधि से अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानो को बाहर रखने का अभाविप कडा विरोध करती है और मॉग करती है कि सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानो मे भी आरक्षण लागू किया जाए, जिससे कि पिछडे समुदाय (SC/ST/OBC) हेतु हजारो सीटे उपलब्ध होगी।

3 सरकारी मेडिकल महाविद्यालयो मे स्नातक (MBBS)एवं स्नातकोत्तर (MD/MS/PG DIPLOMA) आई.आई.टी. व आई.आई.एम. पाठ्यक्रमो मे अधिकतम विद्यार्थियो को प्रवेश का अवसर मिल सके इस हेतु इनमे सीटो की संख्या तथा संस्थानों की संख्या शीघ्र बढाई जाए।

4 उत्तरप्रदेश, केरल, आन्ध्रप्रदेश जैसे कई राज्यो में इस्लाम एव ईसाई पंथो की तथाकथित जातियो को पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति मे सूचीबद्ध किया जाना सामाजिक समता के लिए आरक्षण के संवैधानिक उपचार का उल्लंघन है। अतः इस प्रकार की व्यवस्था बनाकर की जा रही तुष्टीकरण की नीति को रोका जाए।

5 आज तक दिये गए आरक्षण के विविध पहलुओ की समीक्षा करते हुए देश भर मे व्यापक सर्वे कर सरकार एक श्वेतपत्र जारी करे जिससे इसकी वास्तविकता उजागर हो सके।

6 अभाविप यह भी चाहती है कि आरक्षण की सुविधाओ के क्रियान्वयन मे पिछडो में वे जिनको अभी तक इसका लाभ प्राप्त नही हुआ है, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पिछडी जातियों के उन लोगो को जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एव राजनैतिक दृष्टि से एक स्तर पर पहुँच चुके है, उन्हें इससे बाहर रखना होगा। इस हेतु क्रीमीलेयर (Creamy Layer) लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए कर्नाटक राज्य के लिए गठित न्यायाधीश चिनप्पा रेड्डी आयोग की अनुसशाए महत्त्वपूर्ण आधार बन सकती है।

अभाविप का मानना है कि आर्थिक दृष्टि से पिछडे सामान्य श्रेणी के छात्रो को भी अवसरों का लाभ मिल सके इस हेतु उचित प्रावधान किये जाएं।

अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद का मानना है कि आरक्षण जैसे मुद्दे पर केवल राजनेता या सरकारें निर्णय न करें अपितु समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रो के गणमान्य व्यक्तियों जैसे – शिक्षाविद, भूतपूर्व न्यायाधीश, समाजसेवक, समाजशास्त्री तथा छात्र संगठन के प्रतिनिधियों के सहभाग से ऐसे विषयो पर व्यापक राष्ट्रीय बहस के द्वारा निर्णय करे। अभाविप चाहती है कि आरक्षण की बहस रास्तों पर या राजनीति के अखाडो में नही अपितु समाज मे परस्पर चर्चा से चलानी होगी, इस दिशा में परिषद आगामी दिनों में पहल करेगी।

नोट – चिनप्पा रेड्डी आयोग की प्रमुख अनुसशाएं निम्न है –

- आयोग के अनुसार ऐसे किसी भी व्यक्ति को आरक्षण की सुविधाए नही मिलनी चाहिए। जिसके माता–पिता मे से कोई एक सरकारी अथवा सार्वजनिक सेवाओ मे प्रथम या द्वितीय श्रेणी अधिकारी हो अथवा निजिक्षेत्र मे कम से कम द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के बराबर आय पाता हो।
- जिनके माता पिता डॉक्टर, चार्टर्ड एकाउटेण्ट, आयकर परामर्शदाता, आयकर दाता, बिक्रीकर दाता हो।
- जिसके माता पिता दोनों स्नातक हो या जिसके माता पिता व्यक्तिशः अथवा दोनों मिलकर एक निश्चित मात्रा की खेती योग्य भूमि के मालिक हों। ■

DELHI

ABVP seeks probe into funds 'fraud'

Accusing the Delhi University Students' Union (DUSU) of misappropriation of funds totalling Rs. 50 lakhs during the ongoing admissions process, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) has demanded a probe by the Proctor into the matter.ABVPalleged that DUSU president Ragini Nayak got sponsorship cheques issued in her own name and accused her of depositing a cheque for Rs 2 lakhs in her personal account.

ABVP has alleged that the Delhi University Students Union (headed by NSUI) is "misappropriating funds" garnered through sponsorships by various companies. The party, that also has a copy of a cheque worth Rs 2 lakh issued in the name of NSUI president Ragini Nayak by a sponsor, says sponsorships cannot be given in an individual's name.

At a press conference , ABVP state general secretary Nakul Bhardwaj alleged that none of the sponsorship money taken by DUSU had been utilised. "Ragini Nayak is deriving personal benefits. Every year the NSUI has about 30 help desks, this year they have only three. They have not even printed copies of the DUSU information bulletin for the freshers," BhardwajAlleged, demanding an inquiry. ■

राष्ट्रवादी छात्र आंदोलन के 57 वर्ष

–सुभाष शर्मा

9 जुलाई का दिन भारत ही नहीं अपितु समूचे विश्व के छात्र आदोलन के लिए एक महत्त्व का दिवस है, क्योकि इसी दिन 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विधिवत स्थापना हुई थी। परिषद को आज विश्व का सबसे बडा छात्र सगठन बनने का गौरव हासिल है। 13 50 लाख के लगभग सदस्यता और 4,500 स्थानों पर सक्रियता वाला कोई दूसरा सगठन आज विश्व मे नही है। विभिन्न परिस्थितियो मे विश्व के मानस पटल पर कई छात्र सगठन बने, चमके और फिर जैसे ही परिस्थितिया बदली, ये सगठन या तो समाप्त हो गये या अप्रासगिक हो गए। परन्तु छात्र समुदाय की तीव्र प्रवाहशीलता के बावजूद भी पिछले 57 वर्षो से एक स्थाई सगठन के रूप मे विकसित होना विद्यार्थी परिषद सगठन की अदभुत उपलब्धि है और इस महान उपलब्धि की नींव मे है विद्यार्थी परिषद का उददेश्य, उसके सिद्धात और कार्यपद्धति। परिषद् परिस्थितियों या समस्याओ की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ सगठन नही है बल्कि यह तो एक महान उददेश्य की प्राप्ति के लिए शुरू किया गया आदोलन है। अपनी मातृभूमि भारत माता को फिर से शक्तिशाली वैभवशाली व सामर्थ बनाना तथा भारतीय सस्कृति जीवनमूल्यो व दर्शन के आधार पर फिर से सभी व्यवस्थाओ को खडा करना ही परिषद का उद्देश्य है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महान उददेश्य की प्रेरणा से परिषद निरतर अग्रसर है।

> ***आज समाज में छात्र संगठनों के बारे में आमतौर पर धारणा है कि छात्र संगठन सिर्फ तोड़–फोड़, हिंसा, हड़ताल आदि विध्वंसक गतिविधियों में ही लिप्त रहते हैं परन्तु विद्यार्थी परिषद ने अपने 57 वर्षों के गौरवशाली इतिहास से प्रमाणित किया हैं कि छात्र भी रचनात्मक कार्य कर सकते हैं।***

निरन्तर बढ रहे कार्य के साथ–साथ परिषद ने छात्र सगठन का एक नया दर्शन समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। अन्य छात्र सगठनो की तरह परिषद ने छात्रों का यूनियन न बनते हुये एक शैक्षिक परिवार की सकल्पना प्रस्तुत की ऐसा परिवार जिसमे छात्र अध्यापक और शिक्षाविद हैं। परिवार की तरह आपस मे समन्वय करते हुए परिषद शिक्षा क्षेत्र मे परिवर्तन के काम मे निरतर अग्रसर है। परिषद ने छात्रो व अध्यापको और छात्रो व शैक्षिक सस्थानो के प्रशासन मे हितो के टकराव व वर्ग सघर्ष जैसी अवधारणाओं की बजाय भारतीय चिंतन से प्रेरित समन्वय व परिवार की कल्पना को सिद्धात के नाते स्वीकार किया।

आज समाज मे छात्र सगठनो के बारे मे आमतौर पर धारणा है कि छात्र सगठन सिर्फ तोड–फोड हिंसा हडताल आदि विध्वसक गतिविधियो म ही लिप्त रहते है परन्तु विद्यार्थी परिषद ने अपने 57 वर्षों के गौरवशाली इतिहास से प्रमाणित किया है कि छात्र भी रचनात्मक कार्य कर सकते है। रक्तादान कैप प्रतिभा सम्मान समारोह वृक्षारोपण शहीदो की जयतियां मनाना पुस्तक निधि, आपदा राहत समरसता सहभोज, लेख प्रतियोगिता खेल प्रतियोगिता आदि अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से देश के विद्यार्थियो मे एक रचनात्मक दृष्टिकोण निर्माण करने का कार्य परिषद कर रही है।

भले ही आज विश्व मे अन्य सभी छात्र सगठन राजनीतिक दलो की ईकाइयो के रूप मे कार्यरत होगे परन्तु परिषद ने बहुत मजबूती व स्पष्टता से अपने आप को दलगत राजनीति से अलग रखा है। यही कारण है कि जहा अन्य छात्र सगठन अपने राजनीतिक हितो के अनुकूल नीतिया बनाते है वही परिषद हमेशा राष्ट्र व छात्र हित को सर्वोपरि मानकर निर्णय लेती है। परिषद ने राजनीतिक दल का पिछलग्गू न बनते हुए समाज के लिए 'वाच डॉग' की भूमिका को स्वीकार किया है। अपने इन्ही सिद्धातो के कारण आज परिषद ने विश्व के सबसे बडा सगठन होने के साथ–साथ अदभुत सगठन के नाते भी अपनी पहचान स्थापित की है।

आज देश मे जाति, पथ, प्रात व भाषा के आधार पर चलने वाले कई सगठन होगे परन्तु परिषद ने शुरू से ही अपने आप को एक राष्ट्रवादी छात्र सगठन के रूप मे स्थापित किया है। 1949 मे स्थापना के तुरन्त बाद ही देश भर मे परिषद द्वारा 'भारतीयकरण उद्योग अभियान' चलाया गया। जिसमे तीन मागो देश का नाम भारत हो राष्ट्रभाषा हिन्दी हो और राष्ट्रगीत वन्देमातरम हो, के समर्थन मे देश भर मे जनमत सग्रह अभियान चलाया गया। 1970 मे दिल्ली मे एक विशाल प्रदर्शन हुआ जिसमे प्रमुख रूप से तीन मुददे उठाये गये–भारत को परमाणु बम बनाना चाहिये, 18 वर्ष की

आयु में मताधिकार मिलना चाहिये और विश्वविद्यालय प्रशासन में छात्रों की भागीदारी होनी चाहिये। ये तीनों मांगें आने वाले समय में पूरी हुई। 1974 में भारत ने परमाणु विस्फोट किया और भारत परमाणु शक्ति सम्पन्न बन गया। इसी प्रकार 1986 में युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मताधिकार मिला तथा आज थोड़ी मात्रा में ही सही पर विश्वविद्यालय प्रशासन में छात्रों की भागीदारी प्रारंभ हो गई है। निश्चित रूप से परिषद् के लिए यह बड़ी उपलब्धि है।

1973 में गुजरात के राजकोट जिले के मौरवी तहसील के एल ई इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल मेस बिल में बढ़ोत्तरी के विरोध में छात्र आंदोलन शुरू हुआ,जो धीरे–धीरे गुजरात की भ्रष्ट व अक्षम सरकार के विरूद्ध आंदोलन के रूप में पूरे प्रांत में फैल गया। परिषद् के प्रभावी सहभाग से नवनिर्माण आंदोलन के नाम से प्रख्यात यह आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को पद छोड़ना पड़ा। गुजरात आंदोलन की आंच शीघ्र ही बिहार पहुंची और वहां अ.भा.वि.प. की पहल पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर की सरकार की अक्षमता व भ्रष्टाचार के विरूद्ध छात्रों ने संघर्ष का झंडा बुलंद किया। बिहार विधानसभा के घेराव में हजारों छात्रों के एकत्र होने से पूरा देश भौंचक्का रह गया। विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं के प्रयास से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस आंदोलन ने अखिल भारतीय स्वरूप लिया। इस आंदोलन के बढ़ते प्रभाव और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के निर्णय के कारण इन्दिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया। केन्द्र सरकार की तानाशाही के विरूद्ध देश भर में छात्र शक्ति को आंदोलित करने का साहसिक कार्य परिषद् ने सफलतापूर्वक किया। परिषद् के 600 से अधिक कार्यकर्ता मीसा सहित अन्य काले कानूनों के अन्तर्गत महीनों जेल में रहे। दस हजार से अधिक कार्यकर्ताओं ने देश भर में इस आपातकाल के विरूद्ध सत्याग्रह में हिस्सा लिया और अंततः लोकतंत्र की विजय हुई और इंदिरा गांधी को चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। 1977 के इस लोकसभा चुनाव में पहली बार सक्रिय भूमिका निभाते हुए विद्यार्थी परिषद् ने प्रत्यक्ष रूप से नवगठित जनता पार्टी को समर्थन दिया। दलगत राजनीति से दूर रहने के अपने सिद्धांत के बावजूद एक राजनीतिक दल को चुनाव में प्रत्यक्ष समर्थन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि लोकतंत्र की तानाशाही पर विजय होनी चाहिये। चुनावों के बाद भारी बहुमत से जनता पार्टी की सरकार बनी। सारनाथ में जनता पार्टी ने सभी युवा संगठनों को जनता पार्टी के युवा संगठन में विलीन हो जाने को कहा तथा परिषद् के एक कार्यकर्ता की पदाधिकारी के नाते घोषणा भी की, परन्तु विद्यार्थी परिषद् ने इस प्रस्ताव को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया और दलगत राजनीति से दूर रहने के अपने सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देते हुए घोषणा की कि हमारा उद्देश्य सत्ता नहीं समाज परिवर्तन करना है।हमने **'सत्ता नहीं समाज बदलेंगे'** को सिर्फ नारे के रूप में ही स्वीकार नहीं किया बल्कि व्यवहार में भी उतारा और सत्ता के प्रलोभन को अस्वीकार कर दिया।

शिक्षा के विषय पर आंदोलनों और उपलब्धियों की शृंखला इतनी लंबी है कि शायद इसके लिए एक ग्रंथ लिखना पड़ेगा, परन्तु प्रमुख रूप से कहें तो शिक्षा स्वायत्त हो, व्यापारीकरण बंद हो, रोजगारोन्मुख शिक्षा हो, शिक्षा का भारतीयकरण हो, जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च हो, 100 दिन पढ़ाई हो , 40 दिन में परिणाम निकले आदि मुद्दों पर वैचारिक बहस खड़ी करने में परिषद ने सफलता प्राप्त की है।

1996 में भारत में पहली बार विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मीडिया की ओर से इसका जमकर प्रचार अभियान चलाया गया परन्तु विद्यार्थी परिषद् ने इसे देश की संस्कृति के ऊपर आघात मानते हुए बैंगलोर ही नहीं तो पूरे देश भर में जनजागरण अभियान चलाया। परिषद् के कार्यकर्ताओं की ओर से इतना प्रखर जनमत खड़ा कर दिया गया कि बैंगलूर में हो रहे इस समारोह के कई हिस्सों का आयोजन रद्द करना पड़ा और भारी सुरक्षा तथा दर्शकों की कमी के साये में हुये इस समारोह से आयोजकों को इतना घाटा हुआ कि आज तक ऐसी प्रतियोगिता आयोजन करने का साहस इस देश में किसी को नहीं हुआ।

अभाविप इस देश की एकता और अखण्डता के लिए प्रारंभ से ही प्रयासरत रही है। 1961 में हुए गोवा मुक्ति आंदोलन में परिषद् के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका अदा की। 1966 में परिषद् के मुंबई के कार्यकर्ताओं का एक दल अरूणाचल प्रदेश गया। वहां के एक सरकारी अधिकारी ने परिषद् के पूर्णकालिक कार्यकर्ता श्री मदन दास जी से पूछा कि क्या आप भारत से आये हैं? एक सरकारी अधिकारी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न ने

अपने कार्यकर्ताओं को विस्मित कर दिया। ध्यान में आया कि अलगाववाद इतना प्रखर है कि सरकारी अधिकारी भी अपने को भारत से अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है। उत्तर पूर्व प्रांत की इस विस्फोटक अलगाववादी प्रवृत्ति के समाधान के लिए एक प्रकल्प का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया 'अन्तर्राज्य छात्र जीवन दर्शन(SEIL)। इस प्रकल्प के अन्तर्गत उत्तर–पूर्व के हजारों छात्र अब तक भारत के शेष हिस्सों में भ्रमण कर चुके हैं और यहां पर स्थानीय परिवारों से मिले प्यार और सम्मान के कारण आज उत्तर पूर्व में यह लोग राष्ट्रवाद के प्रहरी बन कर खड़े हैं। देश की एकता और अखण्डता के लिये भाषण देने वाले और नारे लगाने वाले संगठन तो बहुत होंगे परन्तु समस्या को समझ कर उसके समाधान के लिए कई दशकों से इस प्रकार का प्रकल्प चलाने वाला छात्र संगठन एकमात्र विद्यार्थी परिषद् ही है।

देश के स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्रांतिकारियों ने युवाओं के समक्ष आदर्श रखा कि देश के लिए मरो और इस प्रेरणा के कारण सैकड़ों युवकों ने अपने जीवन की आहुति दे दी थी। स्वतंत्रता के पश्चात् विद्यार्थी परिषद् ने देश के युवाओं के समक्ष आदर्श रखा–'देश के लिये जियो।' और इसी आदर्श को अपने जीवन में उतारकर हजारों छात्र हर वर्ष परिसरों से निकलकर राष्ट्र पुनर्निर्माण कार्य में जुटते है।

पंजाब में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था और सिख समाज को हिन्दू समाज से तोड़ने की विदेशी साजिश चल रही थी, ऐसे समय में श्री गुरू तेग बहादुर जी के बलिदान को समर्पित **शहीदी संदेश ज्योति यात्रा** निकाल कर पूरे देश में एकात्मता का वातावरण खड़ा करने का साहस परिषद् ने ही किया। जब कुछ दल और संगठन सिक्खों को आतंकवादी के रूप में पेश कर रह थे तब परिषद् ने 1987 में पूरे देश में गुरूद्वारों में जाकर रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया।

1962, 65, 71 और कारगिल युद्धों के समय परिषद् के कार्यकर्ताओं ने नागरिक प्रतिरक्षा, रक्तदान, सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री एकत्र करना आदि कई कार्यों से समाज व सेना का मनोबल बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई। कई सीमा क्षेत्रों में परिषद् के कार्यकर्ताओं ने सैनिक कार्रवाई में भी कई प्रकार का सहयोग दिया। परिषद् की प्रभावी भूमिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संसद पर हुये हमले के बाद सीमाओं पर तनाव की स्थिति में सेना के अधिकारियों ने परिषद् के कार्यकर्ताओं के साथ सम्पर्क कर नागरिक सुरक्षा का दायित्व संभालने की बात की।

प्राकृतिक आपदाओं के समय भी पूरे देश में पीड़ित बहनों व भाइयों की सहायता का भाव जागृत करने का काम परिषद् ने किया। 1979 में मौरवी जिले की बाढ, 1992 का उत्तर काशी का भूकम्प, 1999 में उड़ीसा का चक्रवात, 2001 में गुजरात भूकम्प और 2004 में सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय समर्पण भाव से पीड़ितों की सहायता के लिये तरूणों को प्रेरित कर कई सेवा प्रकल्प चलाये। राहत सामग्री बांटना, लाशों को जलाने से लेकर प्रभावित छात्रों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था करने जैसे कार्य परिषद् के कार्यकर्ताओं ने किए।

विद्यार्थी परिषद् भले ही छात्र संगठन हो पर छात्र आज का नागरिक है सिद्धांत की पार्श्वभूमि में इसने राष्ट्रीय समस्याओं व प्रश्नों पर न सिर्फ अपना मत व्यक्त किया अपितु जरूरत पड़ने पर बड़े–बड़े आंदोलन खड़े किये। 1981–82 में असम में घुसपैठ के विरूद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ। परिषद् ने देश भर में यह अभियान चलाया कि घुसपैठ असम की नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है और इसके लिये 2 अक्टूबर 1983 को गुवाहटी में सत्याग्रह हुआ, जिसमें देश भर से 1000 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आज भी घुसपैठ की समस्या के विरूद्ध असम ही नहीं देश भर में जागरण का काम विद्यार्थी परिषद् कर रही है।

1990 में कश्मीर में आतंकवाद की समस्या गंभीर होने पर परिषद् ने देश भर में आंदोलन किया। जम्मू कश्मीर में एक **तथ्य संग्रह समिति** भेजी गई। दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस समस्या के बारे में देश में जागरण के लिये कश्मीर से विस्थापित छात्र नेताओं का देश भर में प्रवास हुआ। देश में वामपंथियों द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि काश्मीर का आतंकवाद गरीबी व बेरोजगारी के कारण है परन्तु परिषद् ने देश भर में अभियान चला कर समस्या का सही रूप जनता के समक्ष रखा कि यह आतंकवाद इस्लामिक कट्टरता से प्रेरित जेहादी आतंकवाद है। इसी आंदोलन के अंतर्गत आतंकवादियों के द्वारा तिरंगा झण्डा जलाये जाने के विरोध में और श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहराने के लिए देश भर से 10,000 कार्यकर्ता काश्मीर मार्च के लिये जम्मू पहुंचे। भले ही उधमपुर के पास इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया होगा परन्तु

आतंकवादियों के लिए यह संदेश था कि इस देश की युवा शक्ति उनके आतंक से नहीं डरती और उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए सिद्ध है। 1992 में बांग्लादेश को तीन बीघा जमीन दिए जाने के मुद्दे पर भी परिषद् ने देश भर में जागरण किया और तीन बीघा जाकर सत्याग्रह किया।

राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्नों पर विद्यार्थी परिषद हमेशा गंभीर रही है। 1997 में राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर एक अखिल भारतीय सम्मेलन किया गया जिनमें सेना व पुलिस बल के कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इन अधिकारियों ने अपने भाषणों में उल्लेख किया कि उनको हैरानी भी हो रही है और प्रसन्नता भी कि एक छात्र संगठन इतने गंभीर विषय पर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। देश भर में नक्सलवादी आतंकवाद के विरूद्ध परिषद् ने अथक संघर्ष किया है। आंध्रप्रदेश में 34 कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन की आहुति देकर प्रदेश के शैक्षिक परिसरों से इन राष्ट्रद्रोही नक्सलवादियों को उखाड़ फेंका है। जिन परिसरों में नक्सलवाद की फौज तैयार होती थी आज वहां वंदेमातरम् और भारत माता की जय के नारे गूंजते हैं। केरल में भी मार्क्सवादी हिंसा के चलते परिषद् के कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए है, परंतु संघर्ष निरंतर चल रहा है। देश भर में आतंकवादी घटनाओं पर जबर्दस्त प्रतिक्रिया शैक्षिक परिसरों में आज परिषद् के माध्यम से होती है।

देश भर में नक्सलवादी आतंकवाद के विरूद्ध परिषद् ने अथक संघर्ष किया है। आंध्रप्रदेश में 34 कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन की आहुति देकर प्रदेश के शैक्षिक परिसरों से इन राष्ट्रद्रोही नक्सलवादियों को उखाड़ फेंका है। जिन परिसरों में नक्सलवाद की फौज तैयार होती थी आज वहां वंदेमातरम् और भारत माता की जय के नारे गूंजते हैं। केरल में भी मार्क्सवादी हिंसा के चलते परिषद् के कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए है, परंतु संघर्ष निरंतर चल रहा है।

विभिन्न राष्ट्रीय समस्याओं व राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक विषयों पर भी परिषद् ने गंभीर चिंतन किया है। 1990–91 में जब देश में भूमंडलीकरण की आर्थिक नीतियां लागू हो रही थी तो परिषद् ने देश भर में स्वदेशी का आंदोलन चलाया। **स्वदेशी अपनाओ–देश बचाओ** के नारे के साथ देश भर के परिसरों में जनजागरण चला। विद्यार्थी परिषद् ने डंकल प्रस्तावों के विरोध में देश भर में आंदोलन चलाया। 1999 में चीनी उत्पादों के विरोध में देश भर में चेतावनी दिवस मनाया गया। 2000 में अपने आर्थिक चिंतन को और प्रखर करने के लिए आगरा में **राष्ट्रवाद का आर्थिक आयाम** विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। बेरोजगारी के मुद्दे को परिषद् समय–समय पर विभिन्न मंचों पर उठाती रही है। 2003 में मुंबई में **बेरोजगारी समस्या व समाधान** विषय पर राष्ट्रीय संविमर्ष का आयोजन किया गया। 2004 में पेप्सी और कोकाकोला के विरूद्ध अभियान चलाया गया। परिषद् द्वारा अपने प्रस्तावों के माध्यम से सरकार की आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर गलत नीतियां बदलने के लिए विवश करने का कार्य निरंतर चल रहा है।

एक छात्र संगठन के नाते शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं को उठाना और उनको समाधान तक ले जाने के प्रयासों ने ही परिषद् को एक सफल छात्र संगठन के नाते देश में स्थापित किया है। 1986 में जब देश में नई शिक्षा नीति घोषित हुई तो परिषद् ने तीन वर्ष तक विचार गोष्ठियों और प्रस्तावों के माध्यम से देश भर में इस नीति पर राष्ट्रीय बहस खड़ी करने का सफल प्रयास किया। 1988 में जब यह नीति असफल सिद्ध हुई तो परिषद् ने ब्लैक पेपर प्रकाशित किया। 1991–93 में देश भर में परिसर बचाओ आंदोलन चलाया गया। परिसरों में बढ़ रहे थ्री डी संस्कृति यानी ड्रिंक, ड्रग, डिस्को के विरोध में और परिसरों में शैक्षणिक वातावरण खड़ा करने के लिए चलाये गए इस आंदोलन में देश भर में बड़े–बड़े प्रदर्शन हुए। मुंबई में 1,32,000, कर्नाटक में 86,000, उत्तर प्रदेश में 60,000 छात्रों के विशाल प्रदर्शन प्रमुख है।

2002 में शिक्षा व रोजगार को लेकर 75,000 विद्यार्थियों का एक ऐतिहासिक प्रदर्शन दिल्ली में हुआ, जिसमें 12 लाख से अधिक छात्रों का हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपा गया। शिक्षा के विषय पर आंदोलनों और उपलब्धियों की शृंखला इतनी लंबी है कि शायद इसके लिए एक ग्रंथ लिखना पड़ेगा, परन्तु प्रमुख रूप से कहें तो शिक्षा स्वायत्त हो, व्यापारीकरण बंद हो, रोजगारोन्मुख शिक्षा हो, शिक्षा का भारतीयकरण हो, जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च हो, 180 दिन पढ़ाई हो, 40 दिन में परिणाम निकले आदि मुद्दों पर वैचारिक बहस खड़ी करने में परिषद ने सफलता प्राप्त की है। 2001 में देश भर में शुल्क संरचना पर परिषद् ने विस्तृत सर्वे कर आंकड़े इकट्ठे किए, जिनके बारे में एक

उच्च सरकारी अधिकारी ने कहा कि इतने विस्तृत आंकड़े तो सरकार के पास भी नहीं है। गत वर्ष में भी **निजी विश्वविद्यालय** विषय पर गाजियाबाद में, **व्यावसायिक संस्थानों के लिए केन्द्रीय कानून बनाओ** विषय पर बैंगलोर में तथा **शिक्षा को गैट्स से बाहर रखो** विषय पर राष्ट्रीय स्तर की विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया। इन विषयों पर किताबों का प्रकाशन करने का महत्वपूर्ण काम आज विद्यार्थी परिषद् ने ही किया है। शिक्षा राज्यों का विषय होने के कारण कई महत्व के आंदोलन राज्यों में भी हुए हैं। महाराष्ट्र में शैक्षिक विषयों को लेकर मुख्यमंत्री को अपने पद से हटना पड़ा। नागपुर में विश्वविद्यालय के वीसी को अपना पद छोड़ना पड़ा। आंध्र प्रदेश कर्नाटका, महाराष्ट्र आदि प्रांतों में इंजीनियरिंग कालेज में व्यावसायीकरण के विरोध में चले आंदोलन के परिणामस्वरूप करोड़ों रूपये छात्रों को वापस दिलाये गये। वर्तमान में भी केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा के अभारतीयकरण व वामपंथीकरणकी नीतियों के विरोध में शिक्षा बचाओ आंदोलन के अंतर्गत आंदोलन चल रहा है।

परिषद् ने देश के छात्रों के सामने एक नया दर्शन रखा कि छात्र कल का नहीं, आज का नागरिक है और इसलिये उसका भी कुछ दायित्व है। इस प्रकार से छात्रों में समाज के प्रति संवेदनशीलता व दायित्वबोध जाग्रत करने का काम परिषद् ने किया है।

विद्यार्थी परिषद् सामाजिक समरसता के लिए शुरू से ही प्रतिबद्ध है। 6 दिसम्बर 1980 से परिषद् ने डा0 बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाने का क्रम शुरू किया जो आज भी राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख कार्यक्रम है। पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम इतनी बड़ी संख्या में करने वाला परिषद् एकमात्र संगठन हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखने के निर्णय के विरोध में हुये आंदोलन को शांत करने का काम व समाज में इसके लिए स्वीकार्यता बनाने का काम परिषद् ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया। जब नामकरण हो गया तो अंबेडकरवादी कई नेताओंने कहा कि परिषद् के प्रयासों से ही यह संभव हो पाया है। 1990 में चले मण्डल कमीशन विरोधी आंदोलन के समय भी परिषद् ने छात्र समुदाय को दो हिस्सों में बंटने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह आंदोलन सफल नहीं हुआ क्योंकि विद्यार्थी परिषद् ने इसका समर्थन नहीं किया। बिहार का जहानाबाद जब जातिगत हिंसा से जल रहा था तो परिषद् के कार्यकर्ताओं ने जान की परवाह न करते हुए गांव–गांव जाकर पदयात्रा के माध्यम से सामाजिक समरसता का भाव मजबूत किया और आग को शांत किया। परिषद् ने कई बार रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से **हम सब एक हैं** का भाव समाज में जागरण करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

सिर्फ भारत ही नहीं तो पूरे विश्व के छात्र समुदाय को वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा के अंर्तगत् एक मंच पर लाने के लिए 1985 में परिषद् के प्रयास से **विश्व विद्यार्थी युवा संघ(WOSY)** की स्थापना हुई। इस मंच के माध्यम से कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय विषयों, समस्याओं एवं चुनौतियों के बारे में गंभीर चिंतन समय–समय पर होता आ रहा है। 1992 में दिल्ली और 2006 में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ है। श्रीलंका की तमिल समस्या, चीन द्वारा तिब्बत का अधिग्रहण तथा वैश्विक आतंकवाद जैसे कई विषयों पर विचार गोष्ठियों का आयोजन भी हुआ है।

परिषद् ने देश के छात्रों के सामने एक नया दर्शन रखा कि छात्र कल का नहीं, आज का नागरिक है और इसलिये उसका भी कुछ दायित्व है। इस प्रकार से छात्रों में समाज के प्रति संवेदनशीलता व दायित्वबोध जाग्रत करने का काम परिषद् ने किया है। अमेरिका के छात्र आंदोलन से एक नारा निकला था छात्र शक्ति। परिषद् ने इस नारे को पूरा किया छात्रशक्ति –राष्ट्रशक्ति। 1973 में हमने अधिवेशन में यह नारा दिया, जिसके अगले चार वर्ष में देश की छात्र शक्ति ने इस नारे को व्यवहार में बदल दिया और छात्र आंदोलन के दबाव से बिहार, गुजरात तथा केन्द्र की सरकारों को हटना पड़ा।

अभाविप ने पिछले 57 वर्षों में अपनी विभिन्न प्रकार की रचनात्मक, आंदोलनात्मक व प्रतिनिधित्वात्मक गतिविधियों के माध्यम से हजारों कार्यकर्ताओं की शृंखला खड़ी की है। विद्यार्थी परिषद् से जीवन दृष्टि लेने वाले कार्यकर्ता आज समाज के हर क्षेत्र में पहुंच कर उसमें सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए कार्यरत हैं। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्रांतिकारियों ने युवाओं के समक्ष आदर्श रखा कि **देश के लिए मरो** और इस प्रेरणा के कारण सैकड़ों युवकों ने अपने जीवन की आहुति दे दी थी। स्वतंत्रता के पश्चात् विद्यार्थी परिषद् ने देश के युवाओं के समक्ष आदर्श रखा–**देश के लिये जियो**। और इसी आदर्श को अपने जीवन में उतारकर हजारों छात्र हर वर्ष परिसरों से निकलकर राष्ट्र पुनर्निर्माण कार्य में जुटते है। देश की युवा पीढ़ी को ज्ञान, शील और एकता का मंत्र देकर उन्हें भारत माता की सेवा में लगाने का यह राष्ट्रवादी छात्र आंदोलन निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। ■

संपूर्ण समाज का विकास करने में असफल रही है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था

—अतुल कोठारी

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में शिक्षा का व्यापक विस्तार एवं विकास हुआ है। यदि 1950 की स्थिति से आज की तुलना करें तब हम पायेंगे कि जहां 1950 में मात्र 18 विश्वविद्यालय तथा 723 महाविद्यालय थे, वहीं आज देश में लगभग 346 विश्वविद्यालय एवं लगभग 17,000 महाविद्यालय हैं। वर्तमान में उच्च शिक्षा में छात्रों की संख्या भी एक करोड़ से अधिक ही है। गुणवत्ता की दृष्टि से भी हमारे देश की उच्च–शिक्षा का स्तर विश्व के अन्य देशों की तुलना में बेहतर पाया जाता है। हमारे आईआईटी, आईआईएम विश्व के उत्कृष्ट संस्थानों में गिने जाते हैं। आईआईएम, अहमदाबाद को विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थानों में से एक माना जाता है। यहां तक कि आईटी शिक्षा में भी हमने विश्व में प्रतिष्ठा अर्जित की है। इस क्षेत्र में उपलब्धियों का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि थाईलैण्ड के प्रधानमंत्री ने भारत के श्री नारायण मूर्ति को अपना आईटी सलाहकार नियुक्त किया है।

जनवरी 2003 में अमरीका के कैलिफोर्निया में आईआईटी के पूर्व छात्र उन संस्थानों की स्वर्णजयंती के निमित्त एकत्रित हुए थे। उस सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिल गेट्स ने कहा कि आईआईटी संस्थान विश्वस्तरीय संस्थान है और साथ–साथ आगे कहा कि आईआईटी की श्रेष्ठ परम्परा के कारण कम्प्यूटर उद्योग को भारी लाभ प्राप्त हुआ है। आईआईटी के स्नातकों की मांग विश्व में सबसे अधिक है। इससे न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिला है, बल्कि अमरीकी और अन्य देशों को भी फायदा हुआ है।

लेकिन दूसरी ओर ध्यान में आता है कि इतना विस्तार होने के बाद भी हमारे देश के 18–25 आयु वर्ग के मात्र 7 प्रतिशत युवा ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में बाकी 93 प्रतिशत युवाओं के लिए शायद ही कोई योजना है। साथ में यह जानकर और भी अधिक चिंता होती है कि यह विस्तार जो आंकड़ों में इतना व्यापक दिखता है, वस्तुत: असंतुलित है। उदाहरण के लिए यदि देखा जाए तो देश में लगभग कुल 1,400 अभियांत्रिकी महाविद्यालय हैं परन्तु इनमें से 922 मात्र पांच प्रांतों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में सीमित है। यह एक बड़ी विडम्बना है कि देश की योजनाओं के साथ शिक्षा का किसी प्रकार का समन्वय ही नहीं है। विश्वस्तरीय उत्कृष्ट संस्थानों एवं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के बावजूद यदि हम प्रश्न करें कि क्या व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में हमारी शिक्षा सफल हो पाई है, तब इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर पाना कठिन है।

हमारे देश के 18–25 आयु वर्ग के मात्र 7 प्रतिशत युवा ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में बाकी 93 प्रतिशत युवाओं के लिए शायद ही कोई योजना है। विश्वस्तरीय उत्कृष्ट संस्थानों एवं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के बावजूद यदि हम प्रश्न करें कि क्या व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में हमारी शिक्षा सफल हो पाई है, तब इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर पाना कठिन है।

आज की परिस्थितियों में भूमंडलीकरण की चर्चा भी जोरों पर है। हर प्रकार की चर्चा में एलपीजी–लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण एवं ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण छाया हुआ है। इन तीनों बातों से किसी का सिद्धांततः कोई बहुत बड़ा विरोध हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सही अर्थों में इन प्रक्रियाओं का स्वागत भी किया जाता रहा है। भारत में तो आदि–अनादि काल से इस दृष्टिकोण को मान्यता मिली है तथा हमारे पूर्वज इस प्रक्रिया को चलाने में हमेशा अग्रणी रहे हैं। समस्त विश्व में ज्ञान–विज्ञान का आदान–प्रदान आवश्यक है और निरंतर होना चाहिए – Let noble thoughts come from all sides– प्राचीन काल से ही भारत से पूरे विश्व में ज्ञान गया है। विश्व के सभी महान वैज्ञानिकों, दार्शनिकों एवं विद्वानों ने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया है। परन्तु जहां तक वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से समृद्ध देशों द्वारा चलाये जा रहे

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का प्रश्न है, इस पर गहराई से विचार किया जाना अति आवश्यक है। एक ओर तो भूमंडलीकरण की बात की जा रही है परन्तु वहीं दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से समृद्ध देश पेटेंट कानून लागू करवा रहे है। यह एक विशेष प्रकार का प्रोसेस पेटेंट कानून है जिसके द्वारा अविकसित एवं विकासशील देशों की बौद्धिक सम्पदाओं पर एकाधिकार प्राप्त करने का कुचक्र रचा गया है। इस प्रकार का विरोधाभास भूमंडलीकरण के इस नये स्वरूप को संदेहास्पद बना रही है।

एक अन्य चिंताजनक बात यह है कि विश्व व्यापार संगठन(WTO) के तहत विचाराधीन गैट्स(GATS) के अंतर्गत को भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। इन प्रयासों के पीछे प्रमुख तर्क यह है कि शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय आदान–प्रदान को सुसंगत बनाने हेतु इसे गैट्स के अंतर्गत लाना आवश्यक है। लेकिन शिक्षा गैट्स के अंतर्गत नहीं है। तब भी विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के हजारों केन्द्र तथा लगभग 150 विदेशी विश्वविद्यालय हमारे देश में अपना पांव पसार चुके हैं। गैट्स के अंतर्गत 12 सेवायें एवं 161 उपसेवायें हैं तथा शिक्षा उनमें से एक है। शिक्षा के अंतर्गत पांच उपसेवायें हैं जिनमें 1– प्राथमिक शिक्षा, 2– माध्यमिक शिक्षा, 3– उच्च शिक्षा, 4– प्रौढ़ शिक्षा तथा 5– अन्य आते है। गैट्स में चल रहे चर्चाओं में यह ध्यान देने योग्य विषय है कि स्वयं अमेरिका, जिसने इसे लागू करने के लिए दबाव बना रखा है, अभी तक मात्र प्रौढ़ शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए ही अपना प्रस्ताव दिया है।

एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में आज लगभग 48 लाख करोड़ रूपया का निवेश शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है तथा निकट भविष्य में इस आंकड़े के और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। अमेरिका में गत वर्ष निर्यात से लाभ कमाने में शिक्षा का पांचवा स्थान था। भारत में भी कुछ शिक्षाविद्, उद्योगपति, बुद्धिजीवियों का समर्थन इस मत को है कि सेवा के व्यापार से भारत को भी आर्थिक लाभ होने की संभावना है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या किसी संभावित आर्थिक लाभ कमाने हेतु शिक्षा की आधारभूत संकल्पना से समझौता किया जा सकता है? हम बार–बार यह कहते आये हैं कि Education is a charity not a tradable or saleable commodity, तथा इस अवधारणा की पुष्टि इस देश के उच्चतम न्यायालय ने भी स्पष्ट शब्दों में किया है। शिक्षा को व्यापार की वस्तु बनाना, मानना या स्वीकार करना शिक्षा के पीछे के मूल सिद्धांत दर्शन के पूर्णतया विपरीत है। इन्हीं कारणों से शिक्षा को गैट्स के अंतर्गत लाने के प्रयासों का विरोध भारत तथा भारत के बाहर हो रहा है। इन प्रयासों के विरूद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्याभारती, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, भारतीय शिक्षा मंडल तथा संस्कृत भारती जैसे पांच अखिल भारतीय संस्थानों ने दिल्ली घोषणा द्वारा अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं। यहां तक कि पश्चिम के देशो में भी द एसोशिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एण्ड कॉलेज ऑफ कनाडा, द अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन ,दी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज एसोशिएशन तथा दी काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्रीडेशन ऑफ दी यूएस, जैसे संस्थानों ने शिक्षा को गैट्स के अंतर्गत लाने का विरोध करते हुए संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है।

शिक्षा को गैट्स के अंतर्गत लाने पर आपत्तियों का अर्थ यह नहीं कि शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। गैट्स के बिना भी अनेक देशों में दूसरे देश अपने शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित कर पा रहे हैं तथा इस प्रक्रिया को विभिन्न देश MoUs के द्वारा अपनी–अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षा का आदान–प्रदान कर सकते हैं। विभिन्न देशों के भिन्न–भिन्न शैक्षणिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के बीच स्वस्थ स्पर्धा को प्रोत्साहित कर शिक्षा को और अधिक उन्नत एवं समृद्ध बनाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में टिकने के लिए अपनी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना भी आवश्यक है। परन्तु यह धारणा हमारे बीच घर करती जा रही है कि गुणवत्ता निजीकरण के द्वारा ही बढ़ाई जा सकती है। यह धारणा पूरी तरह से सही नहीं है। अभी अमरावती स्पोर्ट्स कॉलेज का एक उदाहरण सामने आया है, जहां लाभ कमाने हेतु इस निजी महाविद्यालय में मानदण्डों को ताक पर रख का प्रवेश दिया जा रहा है तथा बिना उचित प्रशिक्षण के विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा रही है। दूसरी तरफ कालीकट विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से चर्चा के दौरान यह बात प्रकाश में आयी कि निजी महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के अच्छे परिणाम हेतु प्रबंधन स्वयं परीक्षा में अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता है। इस धारणा का एक दुष्परिणाम यह भी है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र से अपना हाथ खींच रही है तथा अनुदानों एवं अन्य वित्तीय सहायताओं को या तो कम कर रही है या खत्म कर रही है। आज जबकि अन्य सभी क्षेत्रों में सरकार अपने खर्चों में लगातार वृद्धि कर रही है तब यह विडंबना है कि शिक्षा पर खर्च कम किया जा रहा है। 1964 में गठित कोठारी कमीशन द्वारा शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करने की अनुशंसा आज तक कार्यान्वित नहीं हो पाई है तथा अब तक यह दर 3 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत के बीच ही है। शिक्षा में सरकार की एक सशक्त भूमिका है जिसे सकारात्मक प्रयासों द्वारा निभाया जा सकता है। शिक्षा में व्यावसायिक, वैज्ञानिक, आधारभूत एवं मानविकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों के बीच संतुलन करने, देश की योजना एवं शिक्षा का समन्वय तथा शिक्षा का व्यापारीकरण रोकने में सरकार को अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा।

(लेखक अभाविप के राष्ट्रीय सह–संगठन मंत्री हैं) ■

अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद

—कमलेश सिंह

भारत माता के चरणों में जीवन ही नहीं, वरन् भारत भूमि को स्वतंत्रता से मुक्त कराने के लिए स्वयं का शीश अर्पित करने वाले अनेक श्रेष्ठ क्रांतिवीरों में चंद्रशेखर आजाद भी एक उदीयमान सूर्य की भांति भारतीय इतिहास में अमर क्रांति शहीद है, जिन्होंने इस देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति का भाव भरने का प्रयास किया और इसका परिणाम 15 अगस्त सन् 1947 को विदेशी दासता से मुक्ति तथा स्वतंत्र गगन में भारतवासियों के सांस लेने के रूप में सामने आया।

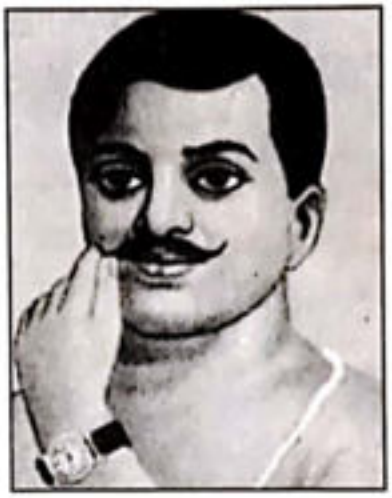

कवि श्री कृष्ण सरल ने सही कहा है 'जिन राहों में छिड़का जाता है गर्म खून, उन राहों पर चलकर आजादी आती है।' युवा होते हुए यदि सांसों में तेजी नहीं, चाल में गति नहीं, शरीर में उर्जा नहीं तो फिर भला युवा, जवान होने का अर्थ ही क्या है? वास्तव में सदैव गतिमान रहने वाला, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन प्रवाह में अपनी क्षमताओं को विसर्जित करना ही युवा होने की निशानी है। ऐसे गतिमान किसी युवा ने सही कहा है :—

देश के हित हम जिएंगे, देश हित मर जायेंगे
देश के जो काम आए, वह जीवन की शान है।

चन्द्रशेखर आजाद का क्रांतिकारी सफर सन् 1921 से शुरू हुआ। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने नौकरी का परित्याग किया और वाराणसी पहुंच गये, उस समय उनकी उम्र केवल चौदह वर्ष थी।

वाराणसी में असहयोग आंदोलन में भागीदारी :— आजाद जब वाराणसी पहुंचे तो देखा असहयोग आंदोलन अपने चरम पर है उनका हृदय उसमें कूदने के लिए मचल उठा ।

उन्होंने शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में आंदोलन के तहत दिए जा रहे धरने में जोर—शोर से हिस्सा लिया। परिणामस्वरूप निर्दयी मजिस्ट्रेट ने उन्हें पन्द्रह बेंतो की सजा सुनाई । मजिस्ट्रेट के सामने बेबाक बयान में उन्होंने अपना नाम **आजाद**, पिता का नाम **स्वाधीनता** और घर का पता **जेलखाना** बताया। पंद्रह बेतों की मार खाते हुए वह प्रत्येक बेत पड़ने पर 'वन्देमातरम्—भारत माता की जय' का जयघोष करते रहे। इस घटना के बाद ही वह क्रांतिकारियों के सम्पर्क में आए और उनके साथ हो गए।

काकोरी षड्यंत्र :— आजाद की जिंदगी का पहला क्रांतिकारी कार्य काकोरी षड्यंत्र के रूप में सामने आया। षड्यंत्र के सूत्रधार और नेता राम प्रसाद बिस्मिल ने एक बारगी आजाद की कम उम्र को लेकर सोचा परंतु उनके द्वारा बेंत खाने की घटना को स्मरण करते ही उन्हें विश्वास हो गया कि आजाद क्रांति के रास्ते से देश को स्वतंत्र करने के मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे।

9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही रेलगाड़ी को काकोरी स्टेशन के करीब रोका। अंदर जाकर आजाद की टुकड़ी ने इसमें रखा सरकारी धन लूटा और वहां से सभी रफूचक्कर हो गए। इस चुनौती को उन्होंने अपनी दिलेरी से कामयाबी का जामा पहना दिया था। काण्ड के बाद प्रायः सभी बड़े क्रांतिकारी पकड़े गए। चन्द्रशेखर आजाद पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सके। यह घटना अंग्रेजी हुकूमत को सकते में डालने तथा भयभीत करने के मामले में बहुत कामयाब सिद्ध हुई।

लाहौर में सांडर्स की हत्या :— 20 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध कर रहे वयोवृद्ध नेता लाजपत राय पर पुलिस अफसर सांडर्स ने अनेक लाठियां भांजीं, परिणामस्वरूप 17 नवंबर 1928 को लालाजी शहीद हो गए। सरदार भगत सिंह ने उसी समय सांडर्स को मारने का प्रण कर लिया था। इस काम को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारी दल ने मुख्य नेता के रूप में चंद्रशेखर आजाद को चुना तथा उन्हें लाहौर भेजा। आजाद ने लाहौर पहुंचकर योजना बनाई तथा तयशुदा अभियान का संचालन किया। उनके नेतृत्व में सरदार भगतसिंह और राजगुरू ने 15 दिसंबर 1928 को सांडर्स को गोली से उड़ाया। उनकी सुव्यवस्थित मोर्चाबंदी और कार्यकुशलता से सफल हुए इस अभियान से लालाजी की मौत का बदला भी चुका लिया गया। सांडर्स हत्या में चार क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरू एवं जयपाल शामिल हुए थे।

असेंबली बमकांड योजना का संचालन :– दिल्ली की केन्द्रीय असेंबली मे लाये गये पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्ड बिल के जरिये अंग्रेज सरकार देश में उठ रहे युवक आंदोलन तथा मजदूरों के हडताल के बाजिब हक को पूरी तरह समाप्त करना चाहती थी। इस विदेशी चाल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केन्द्रीय असेंबली हॉल में बम फेंकने का निर्णय लिया गया। जिसकी योजना चंद्रशेखर आजाद ने बनाई। इसे सफल करने के लिए उन्होंने हाल का निरीक्षण किया था। कार्य को पूरा करने के लिए भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त को चुना तथा साथ ही क्रांति दल ने तय किया कि दोनो क्रांतिकारी आत्मसमर्पण करेंगे। दोनों ने ठीक समय पर बम फेंककर एक बार फिर अंग्रेजी हुकूमत को पसीना–पसीना कर दिया।

आजाद यही नहीं रूके बल्कि फरारी की जिंदगी काटते हुए निरंतर वह भारत माता को मुक्त करने के लिए संघर्षरत रहे। उन्होंने अपना मकसद पूरा करने के लिए आगरा, कानपुर और दिल्ली जाने के बावजूद पुलिस उन्हे पकड नहीं सकी। फरारी के दौरान चन्द्रशेखर जहां रहे, युवाओं को क्रांति के लिए संगठित करते रहे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने पर भारतीय इतिहास के इस महान योद्धा ने अपने शत्रुओं पर पिस्तौल से आग बरसाना शुरू किया। पिस्तौल की गोलियां खत्म होने की स्थिति में अंतिम बची गोली को अपनी कनपटी में दाग लिया।

इस प्रकार जिंदा न पकड़े जाने और हमेशा आजाद रहने का उनका प्रण पूरा हुआ।

सच उनका यह संकल्प कितना दृढ़ रहा होगा–
आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा।

आजाद का काम राजनीतिक विचारों में न उलझकर क्रांतिकारी योजनाओं के निर्माण एवं उन्हें कार्यरूप देना था। उन्होंने विचारों का विश्लेषण नही अपितु विचार को लेकर चलने वाले सैनिकों का संचालन किया। उनके जीवन की शैली विशिष्ट थी। वे जीवन में न्यूनतम आवश्यकताओं की तरफदारी, हर मोर्चे पर संघर्ष के प्रबल पक्षधर तथा जिंदगी को कैसे भी धकियाने की मानसिकता के विरोधी थे। उनका ध्येय मानव जाति को शोषण उत्पीडन और दासता से मुक्त करना था।

अभिशप्त दासता के अंधकार में अपने प्राणों की मशाल जलाकर हमें आजादी का मार्ग दिखलाने वाले चंद्रशेखर आजाद का बलिदान वीरता का वह अमिट शिलालेख है जो भावी पीढियों को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा।

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले।
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा।।

■

जेहाद का नया अवतार

स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)

स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) एक कट्टरवादी मुस्लिम छात्र संगठन है जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के अलीगढ में 1977 में हुई। मोहम्मद अहमदउल्ला सिद्दीकी, प्रोफेसर, पत्रकारिता व जनसम्पर्क विभाग, वैस्टर्न इलीनियस विश्वविद्यालय, मैकाम्ब, अमरीका इसके संस्थापक अध्यक्ष थे।

सिमी का उद्देश्य भारत को इस्लामिक देश बनाना है। प्रोफेसर सिद्दीकी का कहना है कि 1977 में सिमी की स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को शिक्षित करना था। स्टडी सर्किल व भाषणो के माध्यम से स्कूलो, कॉलेजों के छात्रों को इस्लाम की शिक्षाओं से अवगत कराने के लिए सिमी का गठन किया गया था। प्रोफेसर सिद्दीकी के अनुसार वर्तमान में सिमी को कट्टरवादी व आतंकवादी तत्वों ने अपने कब्जे में ले लिया है।

सफदर नागोरी अभी सिमी के मुखिया है। 2001 में पोटा के तहत सिमी पर प्रतिबंध लगने के बाद से नागोरी जेल में है।

उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की प्रांत सरकारों द्वारा, सिमी की साम्प्रदायिक हिंसा भडकाने में शामिल होने संबंधी दी गई रिपोर्टों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा सिमी पर 2001 में प्रतिबंध लगाया गया।

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और असम में इस संगठन का मजबूत आधार बताया जाता है।

सिमी का जमायते इस्लाम, हिज्बुल मुजाहिद्दीन, लश्करे तोएबा जैसे आतंकवादी संगठनों से सीधा सम्बंध है। इसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी संबंध है। पुणे और कानपुर के सांप्रदायिक दंगे में, साबरमती एक्सप्रेस के बम धमाकों में, 2001 में नागपुर मे संघ कार्यालय को बम विस्फोट से उडाने की साजिश में, 2006 में मुंबई ट्रेन बम विस्फोटो सहित कई आतंकी घटनाओं व साम्प्रदायिक दंगों में सिमी का हाथ बताया जाता है।

वर्ल्ड एसेंबली ऑफ यूथ, रियाद, इटरनेशनल इस्लामिक फेडरेशन ऑफ स्थूडेंट्स आर्गेनाइजेशन जैसे संगठन सिमी को धन मुहैया करवाते हैं।

वर्तमान में देश में सिमी के 20,000 सक्रिय सदस्य हैं, जिनमें से 400 पूर्णकालिक कार्यकर्ता है। सिमी के सदस्यों का आदर्श ओसामा बिन लादेन है। ■

अराष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरुद्ध आंदोलन तेज करना होगा : कैलाश शर्मा

मूलतः राजस्थान प्रदेश के रहनेवाले डा. कैलाश शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। परिषद् में वे जयपुर नगर अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। वे वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापक हैं। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और शुल्क संरचना का गहरा अध्ययन किया हैं। 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' के सुभाष शर्मा ने उनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। प्रस्तुत है संपादित अंशः

विद्यार्थी परिषद् के 57 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन वर्षों में कौन सी दो प्रमुख उपलब्धि आप परिषद् की मानते हैं?

मुझे लगता है कि 57 वर्षों तक निरंतर एक छात्र संगठन का बढ़ते जाना अपने आप में एक उपलब्धि है। शायद विश्व में इस प्रकार का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। इन 57 वर्षों में परिषद् ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है, परन्तु सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने देश के अंदर एक सकारात्मक सोच व रचनात्मक दृष्टिकोण वाले छात्र व युवा तैयार किये हैं, जो आज समाज जीवन के हर क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्धता से काम में जुटे हैं। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन कर शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए, इस विषय पर देश में एक बहस उत्पन्न करने का गौरव निश्चित रूप से परिषद को जाता है।

वर्तमान संप्रग सरकार की शिक्षा नीति के बारे में आपका क्या मत है?

जब संप्रग की सरकार बन रही थी उसी समय परिषद् ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद् की बैठक में चिंता व्यक्त की थी कि इस सरकार के आने के बाद शिक्षा में चल रहे भारतीयकरण के प्रयासों को ठेस पहुंचेगी जो आज बिल्कुल सही सिद्ध हो रही है। इस सरकार में वामपंथियों का जिस प्रकार का प्रभाव है उसके कारण से शिक्षा को वामपंथी विचारधारा के प्रसार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एनसीइआरटी की पुस्तकों में से भारतीय संस्कृति, महापुरूषों के बारे में जो आपत्तिजनक बातों वाली पुस्तकें जो राजग सरकार के समय हटाई गई थी उनको फिर से लाया गया है। शिक्षा में से भारतीय मूल्यों, परंपराओं व गौरवमयी इतिहास संबंधी बातों को चुन-चुन कर हटाया जा रहा है। इतना ही नहीं तो वोट बैंक की राजनीति के कारण अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है जो कि राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के लिये खतरनाक हो सकता है।

परिषद् सरकार की इस अराष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में क्या कर रही है ?

परिषद् द्वारा पिछले दो वर्षों से लगातार आंदोलन चल ही रहा है। देश भर में सरकार की इस नीति के विरोध में प्रदर्शन हुये हैं। यहां तक कि कुछ स्थानों पर मानव संसाधन विकास मंत्री को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रकट किया गया है। विचार परिवार के अन्य संगठनों को मिलाकर बने शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के बैनर तले भी आंदोलन हो रहे हैं, जिसका परिणाम भी निकला है। एनसीइआरटी की पुस्तकों में से 39 आपत्तिजनक अंशों को निकालने की बात एनसीइआरटी ने स्वीकार की है, परन्तु अभी भी इस विषय पर आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करना होगा।

देश में शिक्षा का व्यापारीकरण तेजी से बढ़ रहा है। उसके बारे में परिषद् क्या कर रही है ?

परिषद् ने आरंभ से ही शिक्षा के व्यापारीकरण का जबर्दस्त विरोध किया है। 26 नवंबर 2002 की ऐतिहासिक रैली के बाद प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस विषय पर एक टास्क फोर्स का गठन भी किया था। तब से अब तक हम निरंतर इस विषय पर देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। हमने वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री को ज्ञापन देकर मांग की थी कि शुल्क संरचना व प्रवेश प्रक्रिया पर नियंत्रण के लिये केन्द्रीय कानून बनाया जाये। सरकार की ओर से आश्वासन देने और मीडिया के समक्ष घोषणा के बावजूद भी अभी तक यह कानून बनाने की दिशा में सरकार ने प्रयास शुरू नहीं किये है। विद्यार्थी परिषद् इस मांग को लेकर जनमत का दबाव बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त कई प्रांतों में व्यापारीकरण के विरूद्ध सफल आंदोलन हुये हैं और छात्रों को राहत भी मिली है।■

आजादी के उनसठ साल - क्या खोया, क्या पाया?

प्रस्तोता – हिमांशु शेखर

15 अगस्त 1947 का दिन भारतवासियों के लिए ऐसी खुशियां लेकर आया था जिसकी तुलना किसी खुशी से नहीं की जा सकती है। इसी दिन भारत आजाद हुआ था। भारतवासियों में नई उम्मीदें तथा नई शुरूआत की ललक जागृत हुई थी। इस वर्ष 15 अगस्त को हमारी आजादी के 59 वर्ष हो जायेंगे। इस अवधि में भारत ने बेशक काफी तरक्की की है परन्तु कहीं न कहीं सामाजिक स्तर पर कुछ गिरावट भी आई है। इन 59 वर्षों में देश ने क्या खोया, क्या पाया ? इसी मुद्दे पर हमने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बात कर उनकी राय जानने की कोशिश की।

जानकी देवी महिला कॉलेज की लेक्चरर **डॉ0 सीमा शर्मा** का मानना है कि देश ने इन 59 वर्षों में काफी कुछ पाया है। उनके अनुसार भारत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। साक्षरता काफी बढ़ी है। लोग जागरूक हुए है। महिलाओं ने काफी प्रगति की है। लेकिन साथ ही डॉ0 शर्मा इस दौरान आए नकारात्मक बदलाओं को भी रेखांकित करती हैं। उनका मानना है कि आजादी के बाद समाज में रिश्तों की नजाकत पर बुरा असर हुआ है। देशवासियों में संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं समाज में वैचारिक स्तर पर गिरावट आई है। इसके चलते हर स्तर पर संवादहीनता की स्थिति बनी हुई सी लगती है। इससे समाज और परिवार बिखराव के रास्ते पर जा रहा है। यह काफी चिंता का विषय है।

श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज के व्याख्याता **डॉ0 हरनेक सिंह गिल** का मानना है कि इस अवधि में देश ने काफी प्रगति की है, परन्तु कुछ गंभीर मोर्चों पर देश असफल है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद शिक्षा का काफी तेजी से प्रसार हुआ है। भारतीय लोगों ने हर क्षेत्रों में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। दुनिया के ज्यादातर बेहतरीन कंपनियों के वरिष्ठ पदों पर भारतीय ही है। विज्ञान के क्षेत्र में देश ने काफी प्रगति की है। डॉ0 गिल ने कहा कि इस उजाले के पीछे अभी भी कुछ अंधेरा है। गरीबी, बेरोजगारी, असुरक्षा आदि के रूप में व्याप्त इस अंधेरे को जब तक दूर नहीं किया जाता तब तक इस आजादी को असली आजादी नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन 59 सालों में आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं का व्यवसायीकरण हो चुका है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। डॉ0 गिल ने कहा कि इस दरम्यान देश की राजनीति में काफी गिरावट आई है। राजनीति, जो कभी सेवा मानी जाती थी, आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है।

युवा पत्रकार **आनंद कुमार** के मुताबिक भारत ने इन 59 वर्षों में अंतरिक्ष, विज्ञान, खेल, कृषि आदि क्षेत्रों में सफलता अर्जित की है। आज भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही भारत ने इन 59 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को भी पाया है। उन्होंने कहा कि इस दौर में हमने आतंकवाद के चलते काफी कुछ खोया है। हर साल सैकड़ों लोग आतंकवाद का निशाना बन जान गंवा रहे है।

अदिति महाविद्यालय की छात्रा **आइना तोमर** ने कहा कि इन उनसठ वर्षों में भारत ने विश्व समुदाय के साथ कदम से कदम मिला कर चलना शुरू कर दिया है। रक्षा के क्षेत्र में देश ने बहुत सफलताएं पायीं है। खेलों में भी भारत ने उपलब्धियां दर्ज की है। सचिन, गांगुली, गावस्कर, कपिल, कुंबले, सानिया, विश्वनाथन आनंद जैसे खिलाड़ियों ने स्वतंत्र भारत का सर उंचा किया है। वहीं इस दौर में आतंकवाद, साम्प्रदायिकता और जातिवाद बढ़ा है।

श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज के छात्र **आशीष जैन** मानते है कि इन 59 वर्षों में भारत आधुनिकता के मार्ग पर काफी तेजी से अग्रसर हुआ है। इस मार्ग पर आदर्शों को ताक पर रखकर नए सिद्धांतों और मूल्यों की खोज की जा रही है। इन 59 सालों में गांधी कब अप्रासंगिक हो गए पता ही नही चला। संस्कृति और सभ्यता से दूरी बढती जा रही है। इन उनसठ सालों में जनसंख्या में भारी वृद्धि के साथ–साथ अपराधों में भी भारी वृद्धि हुई है।

शकरपुर स्कूल ब्लॉक में रहने वाली गृहिणी **अनीता राणा** भी आजादी को पूर्ण नहीं मानती हैं। उनका कहना है कि आजादी के बाद के वर्षों में महंगाई काफी तेजी से बढ़ी है। आय उस अनुपात में नहीं बढ़ी है। आजादी के वक्त जरूर आम लोगों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाती थी परन्तु आज ऐसा नहीं होता। महिलाओं को अभी भी पूर्ण आजादी नहीं मिली है।

भोपाल से आए छात्र **राजीव कुमार गांधी** के मुताबिक इन उनसठ वर्षों में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की है। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न और सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है। समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। वहीं इस दौर में आतंकवाद और सांप्रदायिकता काफी बढ़ी है। आज धर्म और जाति के नाम पर घिनौनी राजनीति हो रही है।

युवा व्यवसायी **राकेश कुमार** ने कहा कि बेशक आजादी के बाद देश विश्व में महाशक्ति के रूप में उभरा हो परन्तु जमीनी हालत कुछ और ही है। 1991 के बाद से ही देश में बड़े उद्यमियों को तो हर तरह की मदद मिल रही है, परन्तु लघु उद्यमियों को सरकारी मदद केवल कागज पर ही मिलती है। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है पर इस पर कुछ बड़े उद्योगपतियों का वर्चस्व हो गया है। भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसी समस्याओं से भी गंभीरता और सख्ती से निपटे जाने की आवश्यकता है।

इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की **ममता गहलौत** ने कहा कि आजादी के बाद के 59 वर्षों में देश में बड़े–बड़े उद्योग स्थापित हुए है। विदेश व्यापार बढ़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। नई–नई तकनीकी का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। इन वर्षों में देश में भ्रष्टाचार ने काफी तेजी से पांव पसारा है। आज भी काफी लोग अनपढ़ है। बहुत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

बारहवीं के छात्र **अभिषेक कुमार** के मुताबिक भारत ने आजादी के बाद के सालों में बड़ी–बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है। लेकिन अगर गंभीरता से सोचें तो इन उपलब्धियों के पीछे देश की बड़ी विफलताओं की भी लंबी फेहरिस्त है। आजादी के बाद जोर–शोर से हरित क्रांति चलायी गई थी। पर आज भी हमें गेहूं आयात करना पड़ रहा है। देश के किसान गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं। हजारों किसान प्रत्येक वर्ष आत्महत्या कर रहे है। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए आजादी का क्या अर्थ रह जाता है ? हमारा देश आज भी मानसिक तौर पर गुलाम है। हम एक ही परिवार को भारत पर राज करने का अधिकार दे चुके है। पश्चिम की नकल में भी यही गुलामी झलकती है। वास्तविक आजादी के लिए मानसिक धरातल पर चिंतन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। ■

Jammu & Kashmir

ABVP Activists gherao JU Provost Hostel

Jammu UniversityABVP unit gheraoed the provost hostel Prof VK Kapoor for three hours.

The ABVP activists led by President Harpreet Singh Preet and Secretary Mukesh Kumar were demanding early construction of hostel for boys and girls, which was scheduled to be started in the end of January this year but was delayed due to the alleged non-serious attitude university authorities.

The students were demanding hostel for those who live beyond 45 Kms from Jammu.

It was only after the assurance by the given by registrar Prof GS Sambyal, DAA Prof Davinder Singh and DSW Prof Keshav Sharma that the seats in the hostel would be increased and also that the construction girls hostel should be completed six month earlier than the scheduled time that ABVP ended protest. ■

परिचर्चा

शिक्षा में परिवर्तन क्यों होना चाहिए? क्या परिवर्तन होना चाहिए? और यह परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है? इस विषय पर 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' द्वारा परिचर्चा आयोजित है। इस परिचर्चा में पाठकों के विचार आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक 500 शब्दों में अपने विचार स्पष्ट रूप से लिखकर या टाइप कराकर पासपोर्ट आकार के अपने एक चित्र के साथ 30 अगस्त तक प्रेषित करें। प्राप्त उत्तर सितंबर–अक्टूबर अंक में प्रकाशित किये जायेंगे।

सम्पादक
'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
136, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली–110001

समाजसेवा की अद्‌भुत मिसाल-देव संस्कृति विश्वविद्यालय

—आशीष कुमार 'अंशु'

इस देश की शिक्षा गुरूकुल पद्धति पर ही चलानी होगी। नए युग का निर्माण सिर्फ डिग्रीधारी नहीं कर सकेंगे।

यह मानना था वेदमूर्ति, युगऋषि तपोनिष्ठ प0 श्री राम शर्मा का। देव संस्कृति विश्वविद्यालय आचार्य शर्मा जी के इसी दिव्य स्वप्न का मूर्त रूप ही है। उन्होंने वर्षों पहले एक ऐसे विश्वविद्यालय का स्वप्न संजोया था जो नालंदा और तक्षशिला के स्तर का हो। जहां ऐसे महामानवों, देवपुरूषों की पौध तैयार की जा सके जो समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए श्रेष्ठतम नागरिक और प्रखर राष्ट्रभक्त की भूमिका निभा सके।

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ0 प्रणव पण्ड्या के अनुसार देश में विद्यालय और विश्वविद्यालय की कमी नहीं है, पर उनका प्रबंधन, उनकी शिक्षण व्यवस्था बड़े कमजोर स्तर की है। वे आगे बताते है, 'इस आधार पर हम विश्व का नेतृत्व नहीं कर सकते। हमें शिक्षकों को मानव मूल्य आधारित विद्यालय प्रबंधन तथा जीवन विद्या के शिक्षण सूत्रों में निष्णात बनाने का प्रशिक्षण देना होगा।'

शिक्षा और शिक्षण के प्रति इस प्रकार के विचार, समझ और दृष्टि की वजह से ही महज 6–7 महीने में उत्तरांचल के महामहिम राज्यपाल महोदय ने एक अध्यादेश जारी करके देव संस्कृत विश्वविद्यालय को स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रकार यह विश्वविद्यालय विधायी रूप से अस्तित्व में आ गया। जिसे 29 जुलाई 02 को व्यावहारिक रूप से पठन–पाठन प्रारंभ कर मूर्त रूप दिया गया। इसकी देखभाल और खर्च का जिम्मा वेदमाता गायत्री ट्रस्ट शांति कुंज के अधीन है। यह विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित है। यूजीसी अथवा शासन के किसी भी स्तर से यहां कोई अनुदान नहीं लिया जाता। श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा इसका आर्थिक व्यय वहन किया जाता है। विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शैक्षणिक शुल्क नहीं लिया जाता। विद्यार्थियों को मात्र छात्रावास, बिजली, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शैक्षणिक भ्रमण, व्यक्तिगत पुस्तकों का व्यय और परिसर में निवास अवधि के अंतर्गत दैनन्दिन विविध खर्चे खुद वहन करने पड़ते हैं। इसके लिए प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में व्यय लगभग रूपया 7,000/, डिप्लोमा हेतु रूपया 19,000/ एवं स्नातकोत्तर हेतु 1,600 रूपये प्रतिवर्ष तय किया गया है।

	पाठ्यक्रम का नाम	अवधी	सीट
1.	एम.ए./एम.एस–सी. नैदानिक मनोविज्ञान	2 वर्ष	30
2.	एम.ए./एम.एस–सी. मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान	2 वर्ष	30
3.	एम.ए. भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन प्रबंधन	2 वर्ष	30
4.	पी.जी. डिप्लोमा – मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान	1 वर्ष	30
5.	पी.जी. डिप्लोमा – बायो–मेडिकल सिस्टम्स	1 वर्ष	20
6.	पी.जी. डिप्लोमा – बायो–इन्फॉर्मेटिक्स	1 वर्ष	30
7.	सर्टीफिकेट कोर्स – मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान	6 माह	30
8.	सर्टीफिकेट कोर्स – प्राण प्रबन्धन	6 माह	30
9.	सर्टीफिकेट कोर्स – समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन	6 माह	30
10.	सर्टीफिकेट कोर्स – धर्म विज्ञान	6 माह	40

विश्वविद्यालय की सभी योजनाओं के अंतर्गत सभी भारतीय भाषाओं और प्रमुख विदेशी भाषाओं में शिक्षण प्रदान करने की योजना है। नए विषयों में पुरातन एवं आधुनिक विज्ञान, आयुर्वेद सहित वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत चुम्बक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राण चिकित्सा आदि पर शिक्षण के पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। मंत्रयोग, यज्ञविज्ञान और जड़ी बूटी चिकित्सा पर शोध की व्यवस्था की जाएगी। हठयोग, राजयोग, लय योग, मंत्रयोग पर विशेष परियोजनाएं संचालित की जाएगी। विश्वविद्यालय के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

कुलसचिव, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांतिकुंज, हरिद्वार
फोन : 01339–261367, 262094, एक्सटेंशन– 905 ■

मुंबई

परिषद् ने अपना कर्त्तव्य निभाया

विगत 11 जुलाई शाम 6:24 बजे तक सब कुछ हर दिन की तरह चल रहा था। यह समय लोगों के घर जाने का होता है। सभी अपना–अपना काम निपटाकर घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। मुंबई में लोगों के यातायात का प्रमुख साधन लोकल रेल हैं जो कि मुंबई के यातायात की जीवन रेखा है। हर दिन की तरह आज भी लोग इस जीवन रेखा के सहारे अपनों से मिलने अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। अचानक 6 बजकर 24 मिनट एक जोरधार धमाका इसी मुंबई की जीवन रेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेन में खार रोड उपनगरीय रेलवे स्थानक पर हुआ। इससे पहले कि मुंबई पुलिस कुछ समझकर कोई कदम उठा सके, एक के बाद एक आठ धमाके हुए जो मुंबइवासियों को झकझोर कर रख दिया। उल्लेखनीय यह है कि सारे धमाके तीन नंबर की पटरी पर दौड़ने वाली ट्रेनों के आगे वाले प्रथम वर्ग के डिब्बों में हुआ।

इन सभी धमाकों के पश्चात् शासन हरकत में आया और सभी ट्रेने जहां की तहां रोक दी गई। इनमें से एक धमाका मांटुगा रेलवे स्थानक पर भी हुआ जहां अभाविप का केन्द्रीय प्रांत व मुंबई का कार्यालय भी है। सभी कार्यकर्ताओं ने राहत कार्य में शासन का हाथ बटाया। परिषद् कार्यकर्ताओं ने घटना के बाद की जरूरतों को समझा व परिस्थिति अनुसार रक्तदान के लिए मुंबइवासियों के साथ–साथ पास के तीन छात्रावासों में विद्यार्थियों का आह्वान किया। परिणामस्वरूप अस्पतालों में रक्तदान की कतारें लग गई। अभाविप मुंबई ने अपने फोन आम जनता की सहायता के लिए उपलब्ध कर दिए व इन सभी नंबरों को समाचार वाहिनियों पर सहायता नंबर के तौर पर दे दिए। दूसरे दिन सबेरे से देशभर से लोगों के फोन रक्तदान के लिए आने शुरू हो गए। अखिरकार अस्पताल प्रशासन को कहना पड़ा कि खून की जरूरत पूरी हो गई है। आगे आवश्यकतानुसार हम आपसे संपर्क करेंगे।

दूसरे दिन अर्थात 12 जुलाई के दिन अभाविप मुंबई ने अपनी प्रतिक्रिया व इस दर्दनाक हादसे में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए मानव शृंखला के लिए लोगों से आह्वान किया। फलस्वरूप 12 जुलाई की संध्या को मांटुगा स्थानक के समीप यह मानव शृंखला बनी, जिसमें कुल 47 विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता व 50–55 आम जनता शामिल हुई। इसी के साथ श्रद्धांजलि देना भी शुरू हुआ। श्रद्धांजलि देने हेतु सड़क पर चल रही आम जनता ने श्रद्धापूर्वक फूलों को समर्पित किया। इस श्रद्धांजलि व प्रतिक्रिया कार्यक्रम का समापन अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री प्रवीण घुगे जी के भाषण से हुआ।

राजस्थान

'दिशाएं' कॅरियर मेला आयोजित

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जोधपुर द्वारा 16 से 19 जून 2006 तक डॉ एस0 एन0 मेडिकल कालेज परिसर में चार दिवसीय दिशाएं कॅरियर मेला सम्पन्न हुआ, जिसमें शहर के लगभग 60,000 छात्र–छात्राओं, अभिभावकों, गणमान्य नागरिकों सहित शिक्षाविदों की सहभागिता रही। मेले में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो लोकेश कुमार शेखावत एवं महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ एम0 एल0 छीपा, तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रो दामोदर शर्मा, राज्य प्राविधिक शिक्षा मंडल के निदेशक श्री आई आर त्रिवेदी ने मेले को सफल बनाने के लिये सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं मेले में *राष्ट्रीय* विधि विश्वविद्यालय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जयनारायण विश्वविद्यालय ने अपनी स्टाल्स लगाकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। मेले में 64 संस्थानों के स्टाल लगें। वहीं 6 सरकारी विभागों की सीधी भागीदारी रही।

मेले का उद्घाटन– 16 जून को विद्या भारती के प्रांतीय अध्यक्ष प्रो जीवनलाल माथुर ने किया। वहीं जयनारायण व्यास विवि के कुलपति डॉ लोकेश कुमार शेखावत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

प्लेसमेंट समिति द्वारा दिशाएं कॅरियर मेले में युवाओं को सीधा रोजगार देने के लिए प्लेसमेण्ट समिति की स्थापना की गई। प्लेसमेंट समिति के पास 3500 छात्रा–छात्राओं के आवेदन आये, 1200 विद्यार्थियों के साक्षात्कार करवायें तथा 418 विद्यार्थियों को विभिन्न कम्पनियों में नियुक्तियां दिलवायी। मेले में आने वाले कम्पनियों में रिलायन्स इन्फोकॉम, बजाज एल एस, एनआइआइटी, मारूति व टाटा डीलर, सीएमआई पी डब्ल्यू महाराज उम्मेद मिल प्रमुख थी।

राज्य सरकार के यातायात विभाग ने मेला स्थल पर लर्निंग लाइसेंस शिविर लगाकर 572 युवाओं को लाइसेंस प्रदान किये।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय में रोजगार कार्यालय ने मेला स्थल पर अपनी स्टाल लगाकर 650 विद्यार्थियों को पंजीयन कार्ड व नवीनीकरण कार्ड प्रदान किये।

जिला उद्योग केन्द्र– सैकड़ों युवाओं ने जिला उद्योग केन्द्र पर रोजगार हेतु आवेदन किये, ऋण प्राप्ति प्रक्रिया की जानकारी ली।

जिला रसद विभाग– जिला रसद विभाग के विद्यार्थियों के लिए राशन कार्ड बनाने हेतु स्टाल्स लगाई, जिस पर 154 विद्यार्थियों को पंजीयन कार्ड जारी किये गये।

समापन समारोह – 19 जून 2006 को राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण दवे के मुख्य आतिथ्य मे भव्य समारोह संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता तकनीकी विवि कोटा के कुलपति प्रो दामोदर शर्मा ने की। मुख्य अतिथि ने सभी स्टाल्स धारकों को स्मृति चिह्न भेंट किये। अंत मे जिला कलेक्टर श्री नरेशपाल गंगवार ने मेले का अवलोकन करने के बाद भव्य आतिशबाजी एवं नृत्य के साथ मेले का समारोह सम्पन्न हुआ।

हिमाचल प्रदेश

'शिक्षा और रोजगार' विषय पर संगोष्ठी

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं स्वयंसेवी संस्था स्पर्श के संयुक्त तत्वाधान में हिमाचल प्रदेश के वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य एवं बेरोजगारी की समस्या विषय को लेकर 14 जुलाई 2006 को एकदिवसीय सेमीनार का आयोजन किया गया। इस सेमीनार का शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल महामहिम विष्णु सदाशिव कोकजे ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बदलते शैक्षणिक परिदृश्य को देखते हुए एक बेहतर नियोजन की आवश्यकता है ताकि हमें यह पता चल सके कि किस क्षेत्र में कितने प्रोफेशनल की आवश्यकता है ताकि उनके अनुसार ही युवाओं को प्रशिक्षित व शिक्षित किया जा सके। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की राष्ट्रीय सचिव मुक्ता शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थी परिषद मात्र छात्रों के बीच धरने, आंदोलन, तोड़फोड़, हिंसा करने वाला छात्र संगठन न होकर समाज व राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर चिन्ता करने वाला छात्र संगठन है। उन्होंने विद्यार्थी परिषद के इतिहास एवं पृष्ठभूमि पर भी प्रकाश डाला और कहा कि वर्तमान सेमीनार का आयोजन भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है।

इस सेमीनार के समन्वयक प्रो0 चमनलाल गुप्ता ने सेमीनार का विषय रखते हुए कहा कि वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य में बढ़ती बेरोजगारी वास्तव में एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है जिस पर विभिन्न शिक्षाविद, शोधछात्र अपना विषय रखेंगे। इसके उपरांत 12 प्रतिभागियों जिसमें डॉ0 अजय श्रीवास्तव ने हिमाचल प्रदेश में विकलांगों की शिक्षा एवम रोजगार, डा0 सिकंदर कुमार, डॉ0 कुलभूषण चन्देल, प्रो0 सुनील गुप्ता, डॉ0 सुनील सोनी ने वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य व बेरोजगारी, राजेश जसवाल ने हिमाचल प्रदेश में शिक्षित युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी, सुरेन्द्र कुमार ने मूल्य आधारित शिक्षा, नागेश केलकर ने बेरोजगारी उन्मूलन में बैंकों की भूमिका, डॉ0 नयन सिंह एवं डॉ0 सतीश बड़वाल ने अध्यापक शिक्षण का निजीकरण एवं व्यापारीकरण, निर्मल ठाकुर ने बेरोजगारी व शिक्षा तथा डॉ0 वाई0 पी0 शर्मा एवं हरि सिंह ने भारत में अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किये। समारोह सत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो0 राजकुमार भाटिया ने अपने उदबोधन में कहा कि छात्र आज का नागरिक है तथा वह देश व समाज के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने की क्षमता रखता है। इस दिशा में विद्यार्थी परिषद अपनी भूमिका अपनी स्थापना समय 9 जुलाई 1949 से लेकर निभाता आ रहा है। उन्होंने विद्यार्थी परिषद द्वारा 1973–74 के आंदोलनों की चर्चा की जिसने देश में परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाई।

प्रदेश सचिव उमेश दत्त शर्मा ने जानकारी दी कि इस सेमीनार में आए सुझावों को लेकर विद्यार्थी परिषद नवंबर माह में होने वाले विराट छात्र प्रदर्शन हेतु मांग पत्र तैयार करेगी।

पंजाब

अनुशासित छात्रशक्ति से ही होगा राष्ट्र का पुनर्निर्माण

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की स्थापना दिवस पर जालंधर इकाई द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के नाते बोलते हुए पंजाब प्रांत के अध्यक्ष पंकज महाजन ने कहा कि पिछले 57 वर्षों से परिषद् देश के छात्र समुदाय में राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत करने में लगा है। उन्होंने छात्रों को परिषद् की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि पंजाब में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था उस समय राष्ट्र की एकता व अखण्डता की रक्षा के लिए परिषद् ने श्री गुरू तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर शहीदी संदेश ज्योत यात्रा निकाली और प्रदेश में हिन्दू–सिख एकता व सामाजिक सद्भाव के लिए सार्थक प्रयास किये। श्री महाजन ने वर्तमान समय में छात्रों के समक्ष चुनौतियों की चर्चा करते हुए कहा कि आज जिस प्रकार से शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है उससे उच्च शिक्षा आम वर्ग के विद्यार्थियों की पहुंच से बाहर हो गई है। आज अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद भी फीस न होने के कारण शिक्षा से वंचित कई छात्रों द्वारा आत्महत्या करने से हमारे सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। विद्यार्थी परिषद को देश भर में इसके खिलाफ संघर्ष को और तेज कर इसे निर्णायक दौर में पहुंचाना होगा। श्री महाजन ने आये हुये छात्रों को आह्वान

करते हुए कहा कि वह सरकार की रोजगार विरोधी नीतियों के खिलाफ भी एकजुट हों ताकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद सब को रोजगार मिल सके।

इस कार्यक्रम में श्री गुरू जी के जीवन के बारे में आये हुये छात्रों को जानकारी देते हुए संघ के जालंधर विभाग के प्रचारक श्री विजय सिंह ने कहा कि श्री गुरू जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। उन्होंने छात्रों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि श्री गुरू जी ने पूरा जीवन कड़े अनुशासन में जीया और इसी कारण से देश में इतना बड़ा संगठन खड़ा किया जो विश्व में अद्‌भुत है। इस कार्यक्रम में जालंधर महानगर के विभिन्न कालेजों से सैकड़ों छात्रों सहित अध्यापकों, शिक्षाविदों व गणमाण्य नागरिकों ने भाग लिया।

उत्तर प्रदेश

कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित

अभाविप के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नूतन–पुरातन कार्यकर्ताओं का सम्मेलन शिशु मन्दिर, आगरा में पूर्व प्रांतीय संघ संचालक श्री कृष्ण सक्सेना जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के नाते बोलते हुए परिषद् के प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश चन्द्र चर्तुवेदी ने कहा कि परिषद् के कार्यकर्ता जो भी करते है उसको निर्भीकता से करते है। उन्होंने कहा कि परिषद् ने हमेशा ही राष्ट्रीय समस्याओं चाहे कश्मीर समस्या हो या असम में घुसपैठ की समस्या के बारे में जन जागरण किया हे।

उन्होंने यूपीए की सरकार की शिक्षा नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यकवाद की नीतियों से देश की एकता और अखंडता को गंभीर खतरा बन गया है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान बनाने के निर्णय पर प्रहार करते हुए कहा कि परिषद् ने शुरूआती लड़ाई जीती है, परन्तु अभी और भी संघर्ष करना होगा। इस कार्यक्रम में परिषद के नूतन व पुरातन कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

उत्तरांचल

नूतन-पुरातन कार्यकर्ता सम्मेलन

9 जुलाई स्थापना दिवस पर नूतन पुरातन कार्यकर्ता सम्मेलन हल्द्वानी में आयोजित किया गया, सम्मेलन में 150 से अधिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम के उद्‌घाटन सत्र में पूर्व राष्ट्रीय मंत्री श्री तीरथ सिंह रावत मुख्य अतिथि थे तथा अध्यक्षता जिला संघचालक वेदप्रकाश अग्रवाल ने की। मुख्य वक्ता आदित्य राम कोठारी थे।

समापन सत्र में मुख्य अतिथि मोहन पाल, अध्यक्षता गजराज सिंह बिष्ट, मुख्य वक्ता दिनेशजी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने संबोधित किया।

इस अवसर पर दिनेशजी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् राष्ट्रवादी युवाओं की निर्माणशाला है। परिषद् कल्पवृक्ष के समान है। जैसी कल्पना आप समाज व राष्ट्र के लिए करेंगे वैसी शक्ति विद्यार्थी परिषद् से मिलेगी। विद्यार्थी परिषद् देश के पांच हजार से ज्यादा स्थानों पर विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से सकारात्मक सोच वाले कार्यकर्ताओं के निर्माण में लगी है। आज शिक्षा का जिस प्रकार से वामपंथीकरण किया जा रहा है, वह भारत व भारतीयता के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि वामपंथी मानसिकता के लोगों के हाथों में यदि देश की बागडोर रहेगी, तो देश बचा पाना मुश्किल हो जाएगा और शिक्षा के मंदिर भी साम्प्रदायिकता की आग में जल जाएंगे।

अंडमान

श्री गुरूजी प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न

अभाविप की अंडमान इकाई द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर श्री गुरूजी को समर्पित प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल शिक्षा विभाग के निदेशक राजकुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आज प्रतिभावान युवाओं की बहुत आवश्यकता है ताकि दुनिया में तेजी से बढ़ रही तकनीकी का मुकाबला किया जा सके। वहीं चिन्मय मिशन के आचार्य ब्रह्मचारी पुनीत चैतन्य ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि छात्रों को शिक्षा के साथ–साथ समाज और देश के विकास को भी ध्यान रखना चाहिए।

तत्पश्चात संघ के प्रचारक दिलीप घोष ने श्री गुरूजी के जन्मशती के अवसर पर छात्रों को गुरूजी के त्यागमय जीवन से अवगत कराया और उनसे प्रेरणा लेकर उनके पदचिन्हों पर चलने की सीख दी। इस अवसर पर परिषद् के विभाग प्रमुख जी0एस0 पनवर ने भी उपस्थित छात्रों को संबोधित किया।

अन्त में इस कार्यक्रम में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों के अतिरिक्त अभिभावकों, अध्यापकों एवं गणमाण्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। ■

The ideal of tomorrow's India

By Kanwal Bhardwaj

Madhav Sadashivrao Golwalkar, popularly known as Shri Guruji was a man who came to the world with a mission. His personality was reflective of a person eternally engaged in thought. He had a strong will to transform Hindu society from bring meek and submissive to strong and articulate. He knew very well that only strong people have a voice in the world. The strength which he conceptualised was different from that of the religious bigots and bullies who desire to take the world head-on. The Hindutva agenda as visualised by the great sage was devoid of ritual overtones but embraced the wider spans of humanity. Shri Guruji realised that regimentation of thought was equally dangerous, because times may change in the future and the present day ideas may become outdated. He propounded a concept that stood up to the tests of time.

Shri Guruji was a man of the future. He had an intuition as to how the world would shape up and the challenges that the Hindu society would face in successive generations. The present is a testimony to his foresight. History will judge that the political minions critical of his thought would be passed off as non-entities who are masquerading as the saviours of the 'secular' school of thought. The opponents of the Hindutva agenda may simply be bereft of any intellectual facility and befar removed from the cultural realities on the ground.

Much fuss is being made of the word 'secular'. In the seventies and early eighties, the words 'revisionists', 'counterrevolutionaries' and 'bourgeoisie' were in vogue, but are unheard of today. The word 'secular' awaits a similar fate, because its users never seem to understand its spirit. Shri Guruji was often targeted by communists of all hues though the Congress chose to "run with the hare and hunt with the hound". The Congress never strained its vocal chords in disagreeing with Shri Guruji, because like a crafty and mature political outfit it did not want to antagonise the traditional Hindu who always had a soft corner for Shri Guruji's views.

Shri Guruji was the best of both worlds—the ancient and the modern. He was well acquainted with the golden period of our ancient history and the causes that led to our decline and degradation. Individual egos and ambitions were responsible for the 400 years of Mughal rule a about 200 years of Company Raj.

The Mughals were few in numbers at the outset. They wanted to create a society where their minor presence may not give an impression of them being outcasts. Thus for the conversions. The conversions were catapulted on a mass scale using the sword as a barbaric tool. India became a testing ground for the Dar-ul-Harab fantasy and the Hindu its unfortunate victim.

The Company was more crafty. It had a greater insight into the Hindu psyche. For it, the Raj mattered more than religion. It concentrated more on individuals—the feudals, the educated and the ambitious. Shri Guruji analysed that the individual was most vulnerable. The 'Sangh' was formed so that the strength of the units would add up to the collective strength of society. The individual was chosen as a model of physical, mental and moral development.

Shri Guruji pursued the mission of his life with single-minded devotion. His study of human behaviour and personality was remarkable. To sum up his personal qualities of head and heart, he was simple, humble and affectionate. He was an unblemished leader who led by example. He stood tallest among the tall. His communication with the people was lucid, open and philosophical.

The last journey of the great sage immortalised the following lines of Robert Frost:

"The woods are lovely, dark and deep
And I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep." ■

The ABVP made rapid strides since independence of country. Instead of facing the ABVP ideologically in a democratic way, the marxist, Naxal and Islamic goondas had exhibited monumental intolerance and resorted to murder politics. The nation splitters have put medieval barbarism to shame, betraying their Utter contempt for nationalism. Despite the terror, ABVP *Karyakartas* continue to move forward. It is a great saga of sacrifice and martyrdom:-

Sama Jaganmohan Reddy

29.04.1982
WARANGAL

Warangal happens to be the nerve centre of Naxalite insurgency in Andhra Pradesh. The founders of PWG, Kondapalli Sitaramayya and K.G. Satya Murthy used to teach in St. Gabriel School, Warangal.

Nexals take pride in dishonoring national symbols and in ridiculing patriotism. On Independence Day and Republic Day they deliberately would not allow National Flag-hoisting in colleges and hostels. Instead, they fly black flags. Due to the callous attitude of the officials this anti- national stance has been going on unchecked.

On 26 January 1980, in the presence of the Vice- Chancellor, teachers and students, an RSU activist pulled down the National Flag and tried to set fire to it in Kakatiya University, Warangal. Sama Jaganmohan Reddy of ABVP stepped forward, restored the National Flag and gave full- throated slogans Vande Mataram, Bharat mata ki Jai.

Justice Sriramulu, a retired Judge of High Court of Andhra Pradesh, who conducted an inquiery, recommended stringent action against the RSU students. The university removed him from the rolls. A case was registered and Jaganmohan was listed as the main witness. The case dragged on as usual. Despite threats from the Naxals Jaganmohan used to attend the court regularly. The PWG natured a grudge against him and was waiting.

On 29 April 1982, while Jaganmohan was returning home alone from the court in a rickshaw, a Naxal squad attacked with daggers on the busy Hanamakonda main road. He died on the spot. His body was lying in the pool of blood right in the middle of the road for several hours.

Jaganmohan was one of the prominent workers of ABVP. His academic record too was excellent, took his master's degree in economics and was pursuing a law course. He was also preparing for Civil services. He belonged to a rural middle class family, both father (Krishna Reddy) and mother (Anasuya) being government employees. The family sacrificed their only son in the service of the nation. Krishna Reddy fought against the Nizam and spent a year in underground during 1947-48.

Warangal district observed a bandh to protest against the ghastly assassination and the failure of the government to provide protection to witnesses. Jaganmohan's name became legendary and a source of inspirataion to innumerable workers of ABVP. A few weeks later, Shri Atal Behari Vajpayee, President of BJP, visited the family and expressed his condolences during his tour of Warangal. ■

अराष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरूद्ध विशाल प्रदर्शन

—संवाददाता द्वारा

शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति द्वारा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की शिक्षा के अभारतीयकरण, वामपंथीकरण व अल्पसंख्यकवाद की नीति के विरोध में विशाल प्रदर्शन का आयोजन 27 जुलाई, 2006 को जंतर–मंतर पर किया गया।

हजारों की संख्या में शामिल विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों व जनसमूह को संबोधित करते हुए पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री डा0 मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा–2005' के आधार पर बनाया गया नया पाठ्यक्रम वामपंथियों के दबाव में बनाया गया है। राजग सरकार के समय पुस्तकों में शामिल भारतीय इतिहास और संस्कृति के गौरवमयी अध्यायों को हटा कर विद्यार्थियों में हीन भावना पैदा करने वाली बातें पढ़ाई जा रही है।

उन्होंने वर्तमान सरकार पर प्रहार करते हुए पूछा कि पूरी दुनिया में भारत की पहचान जिन जीवन मूल्यों के आधार पर है उनको पुस्तकों में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है। भारत की उज्जवल ज्ञान, विज्ञान की परंपरा से देश के छात्रों को अनभिज्ञ क्यों रखा जा रहा है? भारत की प्रतिष्ठा जिस संस्कृत भाषा से है उसको प्रोत्साहित करने से परहेज क्यों किया जा रहा है? उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो युवा पीढ़ी को देश की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत से जोड़ना ही पड़ेगा।

इस विशाल प्रदर्शन को संबोधित करते हुए लोकसभा में भाजपा के उपनेता श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा कि इतिहास की पुस्तकों में जिस प्रकार की बातें पढ़ाई जा रही हे। उससे किसी भी देशभक्त नागरिक का सर शर्म से झुक जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे किताबों में यह पढ़कर कि "गुरू गोविंद सिंह मुगल साम्राज्य के मनसब थे", बहुत दुःख हुआ क्योंकि जिस महापुरूष ने अपना सारा वंश देश और धर्म के लिए कुर्बान कर दिया उसके बारे में ऐसा पढ़ाने का पाप किया जा रहा है।

शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के संयोजक श्री दीनानाथ बत्रा ने आए हुए जनसमूहों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से इग्नू की एमए इतिहास–1 की पुस्तकों में भगवान शिव को कामुक कहा गया, दुर्गा माता को शराबी व अट्टाहास करने वाली हिंसक महिला दर्शाया गया, भगवान कृष्ण को धूर्त बतलाया गया है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद यह पुस्तकें भारत में नहीं पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही है। दीनानाथ बत्रा ने हिन्दी की पुस्तकों में नक्सलवादी कवि पाश की कविता पढ़ाना व मकबूल फिदा हुसैन जैसे कुख्यात चित्रकार की जीवनी पढ़ाने पर भी विरोध प्रकट किया।

आंदोलन समिति के सह संयोजक श्री अतुल कोठारी ने सरकार की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति का भंडाफोड़ करते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण देश के हितों के साथ खतरनाक खेल खेला जा रहा है। उन्होंने पुस्तकों में औरंगजेब को 'जिंदा पीर' बताने पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि ऐसे जालिम शासक को महिमा मंडित करना शिवाजी महाराज व गुरूगोविंद जैसे राष्ट्रभक्तों को अपमानित करने जैसा है।

उन्होंने संप्रग सरकार द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंरक्षक संस्थान का दर्जा देकर 50 प्रतिशत आरक्षण देना, मात्र अल्पसंख्यक छात्रों के लिए केन्द्रीय बजट में लोक सेवा आयोग की स्थापना करना आदि विषयों पर सरकार को जम कर लताड़ते हुए कहा कि इन सब बातों से अल्पसंख्यकों का कोई भला नहीं होगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि छात्र समुदाय का संप्रदाय के आधार पर विभाजन करने के प्रयास से देश की एकता व अखण्डता को गंभीर खतरा है। उन्होंने आए हुए जनसमूह का आह्वान करते हुए कहा कि यदि सरकार इस राष्ट्र विरोधी शिक्षा नीति को नहीं बदलेगी तो एक प्रखर जन संघर्ष के माध्यम से इस राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक सरकार को उखाड़ फेंकना होगा।

इस विशाल प्रदर्शन में 30 से अधिक शैक्षिक, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। 'शिक्षा का वामपंथीकरण बंद करो', शिक्षा का अभारतीयकरण बंद करो', 'शिक्षा बचाओ–देश बचाओ' के गगनचुंबी नारे के साथ आम जनता ने शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के संघर्ष को व्यापक समर्थन दिया।

इस अवसर पर महेश दत्त शर्मा, श्यामले प्रसाद, अनिल आर्य, विजय सोनकर शास्त्री, आचार्य सोहनलाल, रामधन और जयभगवान गोयल ने अपने विचार व्यक्त किये। ■

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जोधपुर (राजस्थान)
द्वारा आयोजित
दिशाएं कैरियर मेला-2006

आजाद ही
जिया वो,
आजाद ही
मरा वो।

आजाद की
बदौलत,
आजाद आज
भारत।।

क्रांतिकारी चन्द्रशेखर आजाद
जन्मशताब्दी वर्ष
2006–07

स्वतंत्रता दिवस
की
५९वीं वर्षगांठ
के
अवसर पर
सभी देशवासियों
को
हार्दिक
शुभकानाएं

YOUR PASSPORT TO PRIME IT/ITeS JOBS

DOEACC's 'O' 'A' Level

www.anubhav.co.in

ANUBHAV™
The Pathway to Future
An ISO 9001 Institute

MEERUT (ABU LANE) (ACCR No. 0-1298 A-0382)
E-232, 2nd Floor, Uptech Circle, Abu Plaza
Ph. : 0121-2654751, 3257751